during October—December when a large number of copulating pairs can be seen floating near the rookeries on the beach. A large number of hatchlings which fail to enter the sea before dawn are preyed upon by thousands of migratory sea gulls and Mamadian predators like dogs, jackals, hyenas and panthers.

Poachers in big groups from Digha in West Bengal and Balasore in Orissa also catch thousands of sea turtles by nylon nets in violation of the Wildlife (Protection) Act, 1972, and sell them mainly in the Calcutta market. The most unfortunate thing is that the adults and their eggs are also collected by those poachers from the rookeries on the beach and trawlers used by them for fishing in the vicinity of the breeding ground also cause accidental killings of sea turtles.

I suggest that Government of India should send specific instruction to regulate fishing especially during the peak mating and nesting season and for transplanting of the sea nests to protect, the hatchlings from high tide. Coast guard should regulate fishing with the help of speed boats and motor launches in the off-shore area and on the beaches and estuaries during the peak season.

It is necessary to make all possible efforts for the preservation of the sea turtles. Therefore, I further suggest to undertake scientific research on their behaviour pattern, protection in their natural habitat and proper exploitation of the surplus turtles and eggs without affecting the population.

(vii) Need to increase quota of rice for distribution in Kerala

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): The monthly requirement of rice in Kerala for the public distribution system is about two lakh tonnes while the allocations during December, 1982 and January and February, 1983, have been barely 95,000 tonnes per month. It may here be noted that during 1980 and 1981 the monthly allocation was 1,35,000 tonnes. During the five months from December, 1981 to April, 1982, the monthly quota was reduced to 90,000 tonnes, then the Government of India was obliged to raise it to 1,10,000 tonnes from May, 1982. However, once again the Government reduced the monthly quantum arbitrarily to 90,000 tonnes in November, 1982, and then slightly enhanced it to 95,000 tonnes which is the present highly inadequate allocation. The situation has further deteriorated as the arrivals of rice in the State of Kerala has become negligible because of restrictions imposed by the surplus States.

The acute scarcity of rice is having serious repercussions. Let the State not fall a victim to panic and chaos. I, therefore, urge upon the Government of India to raise the monthly allocation so as to restore it at least to the original quota of 1,35,000 tonnes.

Further, the Kerala State Civil Supplies Corporation has sought the permission of the Government of India to buy about 1,00,000 tonnes of rice from the surplus States.

I appeal to the Government of India to see that the food situation in Kerala does not go out of control and that the required measures are taken immediately.

13.39 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने सदन के समक्ष जो भाषण देने की कृपा की है तथा उस के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जी ने रखा है, तथा उस के समर्थन में हमारे प्रो० तिवारी जी ने जो कुछ

[श्री कुंवर रामा]

कहा है, आज मुझे अवसर मिला है कि मैं भी उस के समर्थन में कुछ शब्द कहूं । यूं तो राष्ट्रपति महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में भारत के प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के कार्य-कलापों तथा आगे आने वाले वर्षों में देश के विकास के लिये, देश की मजबूती के सम्बन्ध में गागर में सागर भर दी है, फिर भी हमारे विपक्ष के लोगों को उस से सन्तोष नहीं हुआ है । विरोधी पक्ष के लोगों ने जो कुछ आलोचनाएं की हैं इस अभिभाषण के सम्बन्ध में, उन के संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

यों तो अभी अभी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर था, उस पर कुछ बातें हो रही थीं कि एयर फ्रांस और ईराक एयरवेज के कार्यालयों पर बम फेंके गये और अमेरिकी एम्बेसी और यू०एस० एस०आर० एम्बेसी पर मिसाइल फैंकी गई और राष्ट्रपति महोदय ने भी कुछ इस बात का संकेत दिया है कि इस देश में आतंकवादी, चाहे वे विदेशी हों या देशी स्वरूप हासिल कर रखा हो, सक्रिय हो गये हैं और सरकार को इन के दमन के लिए सारी शक्ति लगानी चाहिए । इस माहौल में जो ये घटनाएं घटी हैं, उन को देख कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत की उदार नीति भी एक कारण बन गई है, जिस की वजह से आतंकवादियों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है और सरकार उस को रोक नहीं पा रही है । इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ऐसी उदार नीति, जिससे देश को खतरा पहुंचे, सरकार को नहीं मानती चाहिए । ऐसी उदार निति से देश की एकता पर प्रहार हो रहा है । पंजाब की हालत आप देख रहे हैं । वहां पृथकतावादी बातें की जा रही हैं । आसाम की हालत आप देखें, वहां उग्रवादी तत्व सक्रिय हो रहे हैं । यह सब उदार नीति के कारण है । ऐसे माहौल में देश तरक्की नहीं कर सकता ? आप यह देखें कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की है । आज हमारा देश औद्योगिक स्तर पर संसार में छठा स्थान प्राप्त कर चुका है, वैज्ञानिक जनशक्ति में छठा स्थान प्राप्त कर चुका है और दुनिया के आधे देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं । विज्ञान एवं कला में भी हमारे देश ने बहुत तरक्की की है । आणविक राष्ट्रों में हमारे देश का चौथा स्थान है और इस तरह से हम प्रगति के रास्ते पर चले जा रहे हैं लेकिन इन आतंकवादियों की वजह से हम अपनी नीतियों को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं और गांवों के उन लोगों को, जिन के लिए हमने योजनाएं बना रखी हैं, उन को उस हद तक लाभ नहीं पहुंचा पा रहा हैं, जितना कि उन को लाभ मिलना चाहिए ।

आज ये टेरोरिस्ट्स विदेशियों की शक्लों में हैं और अपने देश के भीतर भी कुछ ऐसे दलाल हैं और कुछ एसी पार्टियां हैं, जो साम्प्रदायिकता से भरपूर हैं और विदेशी शक्तियों से मिल कर उन्होंने आज देश में एक आतंकवाद का माहौल खड़ा कर रखा है । एशियाड के पूर्व भी इन आतंक-वादियों ने और पृथकतावादियों ने अपनी गतिविधि को बढ़ाया था और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रथम दिन ही रिवाल्वर ले कर आतंक को फैलाने का प्रयास किया था लेकिन भारत सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में उस स्थिति पर काबू पाया और एशियाड बड़ा सफल रहा । उसी तरह से इन आतंकवादियों पर चाहे वे पृथकतावादियों की वजह से और चाहे उग्रवादियों की वजह से, चाहे पंजाब की वजह से या

ग्रासाम की वजह से हो, काबू पाना होगा । पंजाब के माहौल पर कई धार्मिक मांगें थीं । उन मांगों को हमारी प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया है । लेकिन उसके बाद भी ग्रकाली दल के नेता की प्रतिक्रिया देखी । उन्होंने कहा कि यह फ्राड है । क्या यह लोग एक तरह से भारत में माहौल को खराब नहीं करना चाहते हैं जिससे कि देश की एकता खत्म हो, हमारी जो संवैधानिक रचना है, उस पर कुठाराघात हो ? ऐसे माहौल में ग्राज श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कदम उठाया है, उसके लिए इन विपक्ष में बैठने वाले लोगों को भी सहयोग देना चाहिए।

मैं प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती इन्दिरा गांधी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे माहौल में ग्रापकी जो उदार नीतियां हैं, उनमें कुछ परिवर्तन ग्राना चाहिए । ग्रगर उनमें परिवर्तन नहीं लाया गया तो देश की जो व्यवस्था है, जिसको हम 33 वर्षों से चलाते ग्रा रहे हैं, उसको ग्राघात लगेगा । कहा गया है––

विनय न मानत जलदी जड़, गया तीन दिन बीत

बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत ।।

जब तक इस देश में विशेष तत्वों, विशेष लोगों के खिलाफ भय की बात नहीं की जाएगी, उन पर कार्यवाही करने की समुचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक इस देश को टुकड़े होने से नहीं बचाया जा सकता ।

ग्राज कहीं पर धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही है, कहीं पर क्षेत्रीयता की भावना को ले कर लड़ाई चल रही है, कहीं पर भाषा को ले कर लड़ाई चल रही है । ऐसे माहौल में जिन पर भारत की मर्यादा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है, उनकी ग्रपनी उदार नीतियों में ऐसा परिवर्तन लाना होगा जो यहां की जनता को खुशहालरी के रास्ते पर ले जाए ग्रौर भारत की एकता को बरकरार रखे, बनाये रखे ।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी जो ग्रसम में या पंजाब में घटनाएं घट रही हैं, जैसा कि हमने ग्रभी कहा कि ग्रपनी उदार नीतियों में परिवर्तन लाना होगा, वहां यदि ग्रावश्यकता पड़े तो फौज से भी काम लेना चाहिए ग्रौर ऐसे तत्वों को, जो देशद्रोही हैं, खोज कर मौत के घाट उतार देना चाहिए । जो देश की एकता पर खुल्लमखुल्ला प्रहार कर रहे हैं उन के साथ कोई उदारता नहीं बरती जानी चाहिए । भारत माता की वन्दना करने वाले ग्रार०एस०एस० ग्रौर बी०जे० पी० के लोग ग्रपने दृष्टिकोण को बदलें । ग्रगर भारत माता की वन्दना करने वाले लोग ग्रपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तो ग्राज जो ग्रसम की हालत है, पंजाब की जो हालत है, या ग्रभी जो दक्षिण में चुनाव हुए ग्रौर क्षेत्रीयता की भावना को ले कर हुए तो इससे देश टुकड़े में बट जाएगा ।

इन चुनावों में क्या हुग्रा ? बी०जे० पी० या ग्रन्य पार्टी के लोगों ने खुल्लम-खुल्ला इस बात का प्रचार किया कि कांग्रेस के खिलाफ मत दो । ग्रांध्र प्रदेश में ग्रौर कर्नाटक में चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों को सहयोग देने की बात कही । लेकिन इसका परिणाम क्या निकला ? वे कहां रह गये ? उन पार्टियों के सारे उम्मीदवारों की जमानतें जप्त हो गयीं । बी०जे०पी० ने सौ सीटों पर चुनाव लड़ा ग्रौर सौ सीटों पर ही वे हार गये । उनके सारे उम्मीदवारों की जमानतें जप्त हो गयीं । उनका तो मटियामेट हो गया,

[श्री कुंवर राम]

लेकिन कांग्रेस आई तो रही । इस तरह से अपनी गर्दन पर ही उन्होंने चाकू चलाया वे इस बात को भूल गये कि हम भारत माता की वन्दना करते हैं और क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं कि वे इस बात को भी भूल गये कि इससे भारत माता के टुकड़े भी हो सकते हैं और इससे कितना अधिक नुकसान हो सकता है । इस तरह से आसाम भी निकल सकता है पंजाब की क्या दशा हो रही है ? जो मांगें वे कर रहे हैं और आसाम में जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वे हिन्दुस्तान से अलग होना चाहते हैं इसलिए मैं कहूंगा कि इस उदार नीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ताकि इस अखंडता के माहौल को बनाए रखा जा सके अगर इसके लिए कड़े से कड़े उपायों की आवश्यकता पड़े तो वे भी किए जाने चाहिएं हम विरोधी दलों से भी आग्रह करेंगे कि वे प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत करें उन्होंने जो भी स्टेटमेंट पंजाब और असम के बारे दिए हैं, उनमें उन्होंने हिन्दुस्तान की एकता की बात की है इस तरह की अच्छी नीतियों को विरोधी दलों द्वारा बल दिया जाना चाहिए मैं समझता हूं कि अभी आर्थिक क्रांति का माहौल खड़ा हो चुका है और उनकी आलोचनाएं आर्थिक क्रांति पर हो सकती हैं हम अपना सर झुका सकते हैं लेकिन आर्थिक नीतियों को लेकर इतनी तीव्रता से इतने दृढ़संकल्प से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं श्रीमती गांधी के नेतृत्व में उनकी प्रशंसा की जानी चाहिएं जैसा कि मैंने पहले कहा कि विश्व में आणविक शक्ति में हमारा चौथा स्थान है, उद्योग में छठा स्थान है वैज्ञानिक शक्ति में छठा स्थान है दुनिया के छोटे नवोदित राष्ट्र हमारी तरफ देख रहे हैं वे सोचते हैं कि इनसे हमें मदद मिल सकती है एसे माहौल को बरकरार रखने में यदि विपक्ष का सहयोग हमें मिलता है तो दुनिया के शक्तिशाली देश हमारे सामने घुटने टेक सकते हैं इसलिए हमें आज इस माहौल को बरकरार रखना है मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में गागर में सागर भरा है।

मैं विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि वे यहां पर और विधानसभाओं में अपनी आवाज बुलन्द करते हैं कि हम आर्थिक फ्रंट पर प्रगति नहीं कर रहे हैं लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम जो आया है वह एक ऐसा कार्यक्रम है जिस तरह से हनुमानजी धौलगिरि पर्वत को लंका से उठा लाए थे जिस वक्त लक्ष्मण को बाण लगा था वे जख्मी थे सारे स्रोतों को योजनाओं के माध्यम से स्पेशल कंपोनेंट प्लान के माध्यम से देश में, बीस सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा जो सभी अंगों को छू लेती है इस तरह का यह कार्यक्रम लाया गया है यह कार्यक्रम धौलगिरि पर्वत के समान है जो हनुमान जी लाए थे यह बीस सूत्री कार्यक्रम धौलगिरि पर्वत की संजीवनी बूटी है उसके समान है जो आर्थिक शक्ति है उसकी मंशा से ओत-प्रोत है लक्ष्मण रूपी जख्मी गरीब लोगों को कमजोर वर्गों को अनुसूचित जाति और आदिवासी लोगों को बहुत लाभ पहुंचाने वाला है

MR. DEPUTY SPEAKER: You are mentioning my name without taking my permission. Once you mentioned, I was keeping quiet; you mentioned second time. So, I thought, I should put the record straight.

श्री कुंवर राम : मैंने श्रीमान् का नाम जरूर लिया है लेकिन यह कहानी मैं रामायण से निकालकर बोल रहा हूं भारतीय इतिहास के पन्नों से तभी विपक्ष के लोगों का इतिहास बन सकेगा आज अपने देश में आर्थिक लड़ाई चल रही है इसमें पालिटिकल लड़ाई नहीं लानी चाहिए । कांस्टी-

टयूशन व व्यवस्था है उसको फॉलो करने की जरूरत है । आज विपक्षियों का प्रहार हमेशा देश के लिए जो इन्टरेस्ट है, वैसी नीतियों पर होता है । अगर उनका प्रहार जागृत हो, काबिले-तारीफ हो तो माना भी जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं योजना की तरफ जाना चाहता हूं । आज जिस शहर में 12वां अस्पताल है हां 13वां भी बन जाता है । योजना मंत्री को इसकी तरफ देखने की जरूरत है । उनकी दृष्टि वहां जानी चाहिए, जहां सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है वहां सड़क और अस्पताल बनें । जहां हवाई अड्डे हैं, जहां ट्रक और बसें चलती हैं वहीं पर सड़क का निर्माण हो रहा है । आज देहात का पैसा, किसानों और गरीबों का पैसा कर के रूप में सरकारी खजाने में आता है और सरकारी खजाने में आने के बाद वह किस तरह से खर्च किया जाता है, इसको देखने की जरूरत है । योजना विभाग को यह देखना चाहिए कि जहां सड़क और अस्पताल नहीं हैं, वहां पर निर्माण हो । लेकिन, आज इसके विपरीत हो रहा है । इसलिए मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

अब आप शिक्षा पद्धति को ले लीजीए । आज हम अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को भूल चुके हैं । जो शिक्षा साबरमती के आश्रम में या विद्यापीठ में होती थी, वह समाप्त हो गई है । आज सब अंग्रेज़ी-दां हो गए हैं, पश्चिमी विचारों से ओत-प्रोत होते चले जा रहे हैं । इससे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति को भूलते ले जा रहे हैं । मैं कल एक परिवार में गया था, जहां पर एक छोटा बालक शिशु सदन में पढ़ता है । वह हमको नहीं जानता था लेकिन उसने कहा—आपने कीमत क्यों बढ़ा दी ? मैंने कहा, हमने कीमत नहीं बढ़ाई है । उसकी मां ने कहा, तुम कैसे कहते हो कि इन्होंने कीमत बढ़ा दी । उसने कहा, इनकी पोशाक से पता चलता है कि इन्होंने कीमत बढ़ाई है । इस प्रकार की बातें हम देखते हैं । मैं यह सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे स्कूल आपके यहां चल रहे हैं ।

13.59 hrs.

(Shri N. K. Shejwalkar in the Chair)

मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूं जहां सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं और जहां साम्प्रदायिकता की भावना से पढ़ाया जा रहा है । दस बरस के बाद जो संविधान में आपकी धर्म-निरपेक्षता की व्यवस्था है, उस पर प्रहार होने वाला है । जो अंग्रेजी-दां होते चले जा रहे हैं, वे अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और पश्चिम की तरफ देख रहे हैं । आप अपनी शिक्षा पद्धति की तरफ थोड़ी सी दृष्टि रखिए । और उसमें पहल कीजिए ताकि अपनी शिक्षा जनहित में हो, भारतीय संस्कृति के आलोक में हो ।

आवश्यक वस्तुओं की तरफ देखिये । आज बजट भी आने वाला है । रेल बजट पेश हो चुका है । यह सम्भावनाएं बढ़ गई हैं कि इसका बोझ सब पर पड़ेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह बोझ कम से कम गरीबों पर न पड़े । इसका इंतजाम आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य की दुकानों से जो सब्सिडाइज्ड रेट है उस पर उसको मिलना चाहिए । कपड़ा और अन्न अवश्य मिलना चाहिये । सम्भावना है कि बजट में बहुत सी चीजों पर मूल्य बढ़ सकता है । प्रश्न यह है कि खाद्यान्न की आपूर्ति पर गरीबों पर बोझ न पड़े । और अगर उन पर भार पड़ेगा तो प्रशासन पर बुरा असर पड़ेगा ।

[श्री कुंवर राम]

सभापति जी आज पार्लियामेंट के मेम्बर हों, चाहे लोक सभा के या राज्य सभा के, या विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य हों अगर उनका जीवन चरित्र देखें, "हूज हू" देखें, तो पाएंगे कि 95 प्रतिशत सदस्यों का शौंक है हरिजनों और आदिवासियों की प्रगति के लिए काम करना। हम उठाते गये सब ने इसका जिक्र किया कि वह हरिजनों और आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन 33 वर्ष हो गए जो देहात में रहने वाला अनुसूचित जाति का है उसके घर में 4 ईंटें आज तक नहीं लगी हैं। उसके लिए सारी योजनाओं में व्यवस्था की गई लेकिन उसको अफ़सर और कार्यकर्ता खा जाते हैं और अपने मकान बना लेते हैं लेकिन हरिजन का कुछ भला नहीं होता। तो 33 वर्ष की आजादी में एक एक पोलीटीसियन, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वह एम० पी० या एम० एल० ए० हो, सभी ने अपने जीवन चरित्र में इस बात की व्याख्या जरुर की है कि हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये काम करें। तो क्या कहीं मजाक तो नहीं हो रहा है कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ? देहात में रहने वाला जो अमीर किसान है उसके घर में तो ईंटें लगी हैं, लेकिन क्या वजह है कि झोंपड़ी में रहने वाले के घर में जो दिन भर धूप में काम करता है, एक ईंट नहीं लगी है। बड़ा किसान छाता लेकर आड़ी पर खड़ा रहता है और जो मजदूर खेत से घर लौटता है किसान के घर पर बैल बांधने के लिये तो किसान देखता है अपने बैल का पेट। उस इन्सान का पेट नहीं देखता जो जमीन से सोना पैदा करता है। जहां इस प्रकार की मनोवृति हो, श्रम की मर्यादा इस तरह से हो और 33 साल हो रहे हैं हम उनके लिए कहते हैं स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बना दी हैं, लेकिन उसका लाभ उन गरीबों को नहीं मिल रहा है। और अगर लाभ नहीं पहुंचेगा और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के नाम पर सारा रुपया गरीबों का अमीरों के पेट में जायेगा तो आन्दोलन खड़ा हो कर रहेगा यह मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आपका समय हो चुका है कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री कुंवर राम: आज ऐसे गरीबों को जो अपने पेट के लिए आवाज़ उठा लेते हैं तो उसको नक्सली कह कर मार दिया जाता है। इसके लिए सरकार का बार-बार ध्यान दिलाया जा रहा है अगर कोई किसी गरीब को नक्सली कहता है तो पहले उसकी जांच करलें, फिर उसको मारो, —लेकिन सरकार उसको प्रोटेकशन देने में असफल रही है, इसलिए कि आज चुनाव, सस्ता नहीं है, मंहगा है। इन्साफ सस्ता नहीं है, बहुत मंहगा है, इन्साफ ऐसा मंहगा है कि गरीब अगर आज फांसी पर भी चढ़ जाता है तो उसको यह भी पता नहीं है अंग्रेजी भाषा की वजह से कि उसके वकील ने किसी कोर्ट में दलील में क्या कहा है और जज ने क्या फसला किया है और क्यों ऐसा किया है। आज फांसी के तख्ते पर ऐसी व्यवस्था में क्यों वह लटके?

जहां समाज की व्यवस्था एसी हो तो हमें सामाजिक सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और सब तरफ अनुशासन लाने के लिये हमें एक प्लटफार्म तैयार करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। बगैर इन्साफ के देश आगे नहीं चल सकता है। इन्साफ की तरफ सरकार ध्यान दे। अगर इंसाफ होगा तो देश में बहुत से फ्रंट पर जो असुविधाएं मिल रही हैं, वह समाप्त हो जायेंगी।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री कुंवर राम : मैं कुछ मांगे रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

भुखमरी को मिटाना बहुत जरूरी है। इसके लिये कानून बनाना बहुत जरुरी है। नौकरी में अगर किसी परिवार के 3, 3 आदमी लग हैं, या किसी डिपार्टमेंट में 3 आदमी लगे हैं तो उसको खत्म करना चाहिए । जिस परिवार में लोग पढ़े-लिख बठ हुए हैं, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति के पास तीन-तीन मोटर गाड़ी नहीं होनी चाहिएं, अगर हैं तो उसको वापिस लेना चाहिए । किसी के तीन-तीन टेलीफोन लगे हैं तो उसको वापिस लें। समानता की नीति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए ।

भारत एक गांव का देश है । शहर में प्रशासन है, देहात में प्रशासन नहीं है। गांव में आज सुरक्षा नहीं है । देहात की लाइफ को प्रोटैक्ट किया जाये । आज देहात की लाइफ बहुत अशांत है । शाम को कोई बठ नहीं सकता । खेत से किसान वापस जा सकता है या नहीं, यह पता नहीं चलता ।

1983–84 का जो बजट आज मूव हो रहा है, उसमें यह प्रावधान होना चाहिए, गारन्टी दी जानी चाहिए कि गरीब को कपड़ा, खाद्यान्न और दूध सस्ते दामों पर मिलेगा ।

कोसी योजना प्रथम योजना का भाग है, लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हुई, उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ।

राजस्थान में जो नहर योजना है, उसके बारे में एक कहावत है कि बालू सड़े तो सोना झड़े । उसको पूरा करना चाहिए । वह देश के लिये एक बहुत लाभदायक योजना है । वह मुल्क को खाना देगी ।

बिहार की योजनाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बिहर सरकार ने माना है कि सिंहभूम में एक स्टील प्लांट होना चाहिए, कहलगांव में एक ताप बिजली घर की व्यवस्था होनी चाहिए, बरौनी में पैट्रो-कम्पलेक्स होना चाहिए, नवादा में उद्योग होना चाहिए, अपर सकरी योजना सिंचाई की योजना है, जो कि खटाई में पड़ी है, उसे सरकार को आगे निकालना चाहिये । वहां मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त पड़ा है, उसको भरना चाहिए । पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणत करना चाहिये ।

अफसोस की बात है कि कोयलकारो योजना आपकी प्लान में है जिसकी सारी स्वीकृति हो रही है, केन्द्रीय सरकार ने उसका सारा खर्च अपने सिर पर ले लिया है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है। एक क्वैश्चन के जवाब में कहा गया है कि उसके लिये जमीन नहीं मिल पाई है । अगर जमीन नहीं मिल पाई है तो जो बिहांर सरकार के दोषी आदमी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिये ।

नालन्दा पाली इंस्टीट्यूट को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिये । और इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका अभी शिलान्यास हो चुका है, के लिये पूरा फंड देकर उसका निर्माण पूरा करना चाहिए ।

गंगा नदी से बिहार को कोई फायदा नहीं है। बिहार को भी फायदा पहुंचाने के लिए उसमें लिफ्ट इरीगेशन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए । इतनी बड़ी नदी

[श्री कुंवर राम]

होने के बावजूद बिहार हमेशा सूखे के चपेट में रहता है । अतः लिफ्ट इरीगेशन का प्रबन्ध होना चाहिए । मोकामा टाल को दो-तीन फसली बनाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं इतना ही कहकर बैठ जाऊंगा कि उच्च न्यायालयों में भी उसी प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जिस प्रकार से अन्य जगह है । कांस्टीट्यूशनल प्राविजन होने के बावजूद उच्च न्यायालयों में अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं है अतः इसके लिए यदि कोई अमेन्डमेन्ट करने की आवश्यकता हो तो उसको करने के पश्चात् आरक्षण की व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको बार-बार जो घंटी बजाने का कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूं ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : (चितौड़गढ़) : सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने कृपापूर्वक जो अभिभाषण सदन के सम्मुख दिया है उसपर रखे गए धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं ।

हम पिछले तीन वर्षों से आत्मनिर्भता की ओर निरन्तर बढ़ रहे हैं परन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष को हमारी उपलब्धियां दिखलाई क्यों नहीं देती हैं । जो कठिनाइयां देश के सामने हैं उनको तो वे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बतलाते हैं लेकिन जहांतक हमारी उपलब्धियों का सवाल है वह उनको दिखाई नहीं देता । आज हम 90 प्रतिशत आत्मनिर्भता की ओर बढ़ चुके हैं । हमारे वैज्ञानिकों, किसानों, टैक्नीशियनों ने कितनी अधिक प्रगति की है इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता । अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने जो सफलतायें प्राप्त की हैं वह एक कीर्तिमान हैं । रोहणी 560 को भेजकर स्पेस में जाने की हमारी जो तैयारियां हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर अनुसन्धान के लिए जो दो अभियान दल गए हैं उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता । उन्होंने भी नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं । इसके साथ ही साथ हमने समुद्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक स्थान प्राप्त कर लिया है । इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि एशियाड है जिसने हमारे लिये ओलंपिक का द्वार खोल दिया है ।

यदि हम पिछली सरकार की बातों का अवलोकन करें तो पता लगेगा कि उस समय हमारे अन्तर्राष्ट्रीय संबंध बहुत बिगड़ गए थे परन्तु पिछले तीन सालों में श्रीमति इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे आन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध न केवल सुधरे हैं बल्कि उनमें एक नया कीर्तिमान सामने आया है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि भारत में सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होने जा रहा है । इतिहास में पहली बार सौ राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में यहां भाग लेंगे । विकासशील राष्ट्रों के बारे में, उनके आर्थिक विकास के बारे में और उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में यह सम्मेलन चर्चायें करेगा । पहले यह सम्मेलन बगदाद में होने जा रहा था, अक्तूबर, 1982 में यह तय हुआ कि सम्मेलन दिल्ली में किया

जाए, उसके पश्चात् इतने कम समय में इतनी अधिक तयारी कर ली गई—इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता का विश्वास प्राप्त करना। दक्षिण में क्षेत्रवादी भावनायें फैलाने के कारण कुछ हमारी उपलब्धि नहीं हो पाई थी। परन्तु दिल्ली की जो जनता है, जिसे हम मिनि-भारत कह सकते हैं, हिन्दुस्तान का मस्तिष्क कह सकते हैं, उसने यह दिखा दिया कि आज देश की जनता श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ है। उसी का यह परिणाम हुआ कि भारतीय जनाता पार्टी के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देने का नाटक करना पड़ा। मैं यह कहना चाहूंगी कि असम में आज दो-तिहाई बहुमत के साथ श्री हितेश्वर सैक्या द्वारा सरकार बना ली गई है, इसको देख कर विरोधी पक्ष के लोगों में बहुत अधिक क्षोभ है। असम में चुनाव कराना एक संवैधानिक अनिवार्यता थी। हम संविधान से आगे नहीं बढ़ सकते थे, परन्तु राजनीतिक स्वार्थों की खातिर वहां हत्याओं का जाल बिछा दिया गया, लाखों-करोड़ों रुपयां की सम्पत्ति की होली जलाई गई। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और बंगलादेश में चुनाव कराने के लिए वहां की जनता आन्दोलन कर रही है, जब कि हमारे देश में ऐसी कई पार्टीज थी, जिन्होंने चुनाव न कराने के लिए अपने पक्षधर को मजबूत किया। लगातार वहां तीन वर्ष से समझौते को बात हो रही है। कभी सन-आफ-सायल के नाम पर झगड़ा, विदेशी नागरिकों के नाम पर झगड़ा, आखिर समझौते की भी एक हद होती है। इस आधार पर कब तक चुनाव को रोका जा सकता था। यह कितनी बिडम्बना है कि देश का नागरिक दूसरे राज्य में जाने पर विदेशी हो जाए। असम में बिहारी, बंगाली और राजस्थानी विदेशी हो जायें। इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जो अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी और लोकदल के लोगों ने समर्थन किया।

विरोधी दल के लोग अपने आपको गांधीवादी कहते हैं। उन्होंने गांधी जी की समाधि पर जा कर इस बात की शपथ खाई थी कि हम गांधी जी के सिद्धान्तों को मानेंगे। गांधी जी ने चोर-चोरी कांड के नाम पर अपना सारा आनदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इन पार्टियों ने इस आन्दोलन में और अधिक घी डालने का काम किया। मैं कहना चाहती हूं इस प्रकार की गतिविधियां उन्हें शोभा नहीं देती हैं। दूसरी ओर अब अकालियों के नाम पर आग सुलगाने की तैयारी की जा रही है। मैं ज्यादा इस बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहती हूं। केवल राजस्थान से सम्बन्धित जो बात है, सिर्फ उस० ज़िक्र करना चाहूंगी। अकालियों की मांग है कि रावी-ब्यास का पानी जो राजस्थान को दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाए। इस प्रकार की बात राजस्थान के लिए कहना, जो कि सूखे और अकाल से ग्रसित रहता है, एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। 31 दिसम्बर, 1981 को समझौता हुआ था। उसके उपेक्षा करना एक बहुत ही घोर निराशा की बात है। 1955 में यह तय हुआ था कि राजस्था को 87 लाख घन-फुट पानी दिया जाएगा। इसके बाद 31 दिसम्बर, 1981 में यह निर्णय लिया गया कि एक लाख यूनिट पानी दिल्ली के लिए कम कर दिया जाएगा। हमने इसको मान लिया लेकिन फिर भी इस बात पर अड़े रहना कि राजस्थान को पानी कम दिया जाए, उचित नहीं है। राजस्थान के हिस्से का एक बूंद पानी भी यदि कम किया गया तो राजस्थान की जनता के लिए यह

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

घोर अन्याय होगा। इसी के आधार पर हमने राजस्थान कनाल योजना बनाई है, जिस पर हम अब तक 550 करोड़ रु० से 600 करोड़ रु० तक व्यय कर चुके हैं। इस योजना को हमने अपनेखून-पसीनेसे सींचा है। दूसरी योजनाओं का काट कर इसकय बनाने की कोशिश की है लेकिन आज यदि पानी को कम कर दिया गया तो यह राजस्थान की जनता के लिए खून-खोलने की बात हो जाएगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजस्थान का जब खून खौल उठता है तो उस का क्या परिणाम होता है। इसलिए मैं आप के माध्यम से अकालियों से कहना चाहूंगी कि राजस्थान के हिस्से का एक बूंद पानी भी कम करना उन के लिए बहुत ही विडम्बना होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगी—रावी-ब्यास नदियां का उद्गम .....

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो0 निर्मला कुमारी शक्तावत : मैंने तो अभी दो मिनट ही बोला है।

सभापति महोदय : आप की घ शायद अलग है, यहां की घड़ी में 9 मिनट हो चुके हैं, आप को 10 मिनट तक बोलना है।

प्रो0 निर्मलाकुमारी शक्तावत : मैं यह निवेदन कर रही थी कि रावी ब्यास नदियों का उद्गम पंजाब में नहीं है बल्कि हिमालय में है, जम्मू काश्मीर में है, इसलिए उन का एक बूंद भी पानी कम करने का अधिकार नहीं है। पंजाब के पास पानी पहले हग बहुत ज्यादा स्रोत हैं अण्डर-ग्राउण्ड वाटर भी है, इस लिये 1955 के समझौते से मुकरने वाली बात उनके लिए शोभा नहीं देती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजस्थान के ६८६ से का पानी कम नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम हमारी महान उपलब्धि है। इस के माध्यम से हमारे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को जितना फायदा पहुंचा है, इतिहास साक्षी है। किसी भी युग में किसी भी शासक द्वारा इस प्रकार का फायदा गरीबों को नहीं पहुंचा। परन्तु इस बीस सूत्री कार्यक्रम के सामने भी एक प्रश्न-चिह्न लग जाता है और वह है—पावर-कट। राजस्थान में बिजली की इतनी ज्यादा कमी है कि तमाम इण्डस्ट्रीज़ में 100 प्रतिशत पावर-कट है। हमारे किसानों ने अकाल से जूझते हुए अपने खून-पसीने से जो थोड़ी-बहुत फसल बोई थी वह भी बिजली के अभाव में खूब सूख रही है। राजस्थान को 200 लाख यूनिट्स की आवश्यकता है लेकिन उसे मिल रहा है—केवल 90 लाख यूनिट। इसलिए मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी बिजली की कमी दूर की जानी चाहिए। बदरपुर से भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। राणा प्रताप सागर एटामिक प्लांट बहुत दिनों से खराब पड़ा है। उस की एक इकाई शुरू होती है तो दूसरी खराब हो जाती है। कुछ दिन पहले 25 दिनों से खराब एक इकाई ठीक हुई थी। कोटा थर्मल पावर प्लांट (ताप बिजली घर) की स्थापना की गई थी और यह आशा थी कि वह 15 जनवरी तक शुरू हो जायगा, लेकिन वह भी नहीं हो पाया।

राजस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग में लिगनाइट का बहुत अधिक भण्डार है। वहां पर फालना में ताप-बिजली-घर की स्थापना की जा सकती है। यहां एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूं—पावर-जैनरेशन का काम केन्द्रीय सरकार

को अपने हाथ में लेना चाहिए। इस को केन्द्रीय सूची में रखा जाना चाहिए ताकि सभी राज्यों की समस्या का समाधान हो सके।

आज हमारे पास थोरेनियम, यूरेनियम और प्रोटेनियम की कमी नहीं है। अथाह भण्डार हमारी भूमि के गर्भ में छिपा हुआ है। इस के आधार पर 8 इकाइयां लगाई जा सकती हैं। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान के कई भागों में जिंक निकलता है। दरीबामाइन्ज़ और अगूचा के आधार पर सुपर-जिंक के कारखाने की स्थापना के बारे में काफ़ी लम्बे समय से चर्चा चल रही है। टैक्नीशियन्ज़ ने भी राय दी है कि इस के लिए सब से उपयुक्त स्थान राजस्थान का चितौड़गढ़ है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उस ऐतिहासिक स्थान पर ऐसा उद्योग लगाने से वहां की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और जब टैक्नीशियन्ज़ ने ऐसी राय दे दी है तो सरकार को जल्द से जल्द स्वीकृति दे देनी चाहिए।

राजस्थान में पिछले पांच सालों से भयंकर सूखा फैला हुआ है। वहां की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, किसी तरह की फसल वहां पर पैदा नहीं हो रही है। अकाल राहत के नाम पर कुछ काम शुरू किये गये थे, लेकिन राजस्थान सरकार की मांग थी— हमारे यहां 22 हज़ार गांव तथा डेढ़-करोड़ व्यक्ति अकाल से पीड़ित हैं। उनके लिए 215 करोड़ 51 लाख रुपये मांगे थे अकाल राहत के लिए परन्तु केन्द्र सरकार से केवल 29 करोड़/ 86 लाख रुपये ही मिले। यह बहुत कम राशि है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि राजस्थान भयंकर सूखे की चपेट में है और उसे बचाने के लिए निश्चित तौर पर केन्द्रीय सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए।

किसी भी देश की शान जाने के लिए, उस के विकास के लिए तीन आधार-शिलाएं हैं। एक तो स्कूल, दूसरी पंचायत और तीसरी सहकारिता। इन तीनों ही क्षेत्रों में हम ने बहुत अधिक काम किया है और राजस्थान सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया है और वह है 'प्रशासन गांवों की ओर' और आने वाले वर्ष में राजस्थान की जनता को एक नये उपहार के रूप में यह एक नया प्रयोग वहां पर शुरू किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी तक गांव के व्यक्ति को एक महंगी, विलम्बकारी न्याय व्यवस्था मिली है और उस से वह बहुत पीड़ित रहा है। कचहरी और वकीलों के चक्कर लगा लगा कर वह परेशान हो जाता है। इस नये कार्यक्रम के अनुसार उसे इन परेशानियों से छुटकारा मिला है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इस प्रकार का कार्य-क्रम 'प्रशासन गांवों की ओर' राजस्थान के अलावा देश के अन्य प्रान्तों में भी शुरू किया जाना चाहिए ताकि वहां पर गरीबों को आसानी से न्याय मिल सके। छोटी छोटी खामियों की वजह से वे जमीन के मालिक नहीं बन पाते और जमीन का विकास करने के लिए वे बैंकों से लोन नहीं ले पाते। इन सब सुविधाओं को जुटाने के लिए 'प्रशासन गांवों की ओर' जैसे कार्यक्रम के लिए सभी प्रदेशों को आगे बढ़ाना चाहिए।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो विरोधी पक्ष है, उसको निकारात्मक भूमिका छोड़ कर एक रचनात्मक सहयोग हमको देना चाहिये जिससे हम सब मिल कर देश को आगे बढ़ा सकें। यदि निकारात्मक भूमिका बनी

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

रहेगा, और बम्बई में जो मजदूरों की हड़ताल कपड़ा मिलों में चल रहा है, अकालियों की जो मांगें हैं या आसाम में जो चिंगारियां दहक रही हैं, उन में यह घी डालने का काम होगा ।

इन शब्दों के साथ, राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया है, उस के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): I do not want to be unduly harsh, but look at the clock. For a long time, there is no Minister of the Cabinet rank. I waited for the customary lunch hour to be over. After all, we can understand that the sanctity of this House has been much undermined by the frontal attacks on democracy and scuttling the sanctity of the Budget. Still a residuary honour is left at least. This is not the first time that such a situation has arisen on the debate on the President's Address. Therefore, my strong plea is to adjourn the House till some Cabinet Minister has the courtesy to enter and see that the honour and respect of the House is duly maintained.

MR. CHAIRMAN You have expressed your views very strongly and forcefully. I think, leave it to them to realise it.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): The Cabinet Minister is just coming.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): I also share the concern of our distinguished friend, Mr. Banatwalla that the Government should not show this kind of attitude when an important document like that of the President Address is being discused.

However, I rise to express my regret that the President's Address, as a matter of fact, does not reflect the real situation now prevailing in the country. Because of limitation of time, you cannot except me to give in details as to how I made that observation that the President's Address does not reflect the actual reality of life in the country. I will only put across two or three instances which I believe would convince the House that the President's Address lacks the reality which obtains today. The President has been pleased to remark on page No. 1 paragraph 2 that the public distribution systhem was expanded and made more efficient. I think you would permit me to explode this myth. If you are aware of the actual state of affairs regarding the stock of the foodgrains in our country, you would know that the total foodgrains stock was no more than 15.5 million tonnes as on July 1, 1982. This was the stock with the Government. Out of this, 10 million tonnes was wheat and about 5 million tonnes was rice. You will be astonished to know that 50 per cent of the stock was not fit for human consumption. So, naturally the Government stock did not exceed more than 10.5 million tonnes as on July 1, 1982. As you are aware, the offtake from public distribution system is currently reported to be of the order of 15 million tonnes per annum which will be the stock position with the Government till we reach May 1, Rice procurement can never exceed more than five million tonnes in our country. This year it is believed, and it should be accepted also, that because of the drought conditions prevailing over a large part of the country, the rice stock cannot exceed more than 3 million tonnes. By this time the Government have, in their wisdom, imported 2.5 million tonnes of wheat from foreign countries. Naturally, the total food stock left till May 1 would be 10.5 million tonnes which would be the residuary plus 3 million tonnes which might be in the form of procurement of rice and 2.5 million tonnes by way of imports. Out of thee, the total requirement for the public distribution system will come to 12.5 mil-

lion tonnes, leaving only 3.5 million tonnes for the rest of the year. I think, the President should have known all these things that the stock position of the country is very precarious and there is no possibility for the continuance of the supply through the public distribution system. My friend Banatwalla was mentioning about the Kerala situation. I can also mention about the situation in West Bengal. There are vast areas of our country which are denied the supply of foodgrains through public distribution system. Even if we accept that this public distribution system can be continued, I have got great doubts that it will be possible because of the food situation which I have just now mentioned. There are other points also to be taken into consideration. If there is no cheaper rice available outside the scope of public distribution system because public distribution system is not there all over the country and is limited only to towns and urban areas *(Interruptions)*

PROF. N. G. RANGA (Guntur): It is in rural areas also.

SHRI CHITTA BASU: Not so much. You will agree with me that we have not been able to cover the entire rural areas. This is the reality of the situation. You may deny the reality—you may have that satisfaction; I do not grudge it—but the reality is that the public distribution system does not cover the far-flung villages of our country. Therefore, even if you continue the public distribution system, there is need for providing cheaper foodgrains for the rural masses, which means the necessity for larger procurement. I say that the Government have failed to make adequate arrangements for mopping up the surplus from the cultivators.

Then there is the question of purchasing power. Unless you provide the purchasing power to the rural masses, even if rice is available, they cannot purchase it. As a matter of fact, while the necessity or the need of the hour is to extend the NREP, I am bound to say that it is being whittled down. Therefore, the satisfaction expressed by the President is in no way related to the actual situation of our country, particularly with regard to foodgrains.

The Address says:

> "This year the Central Government would be releasing to the States about Rs. 7,000 million (Rs. 700 crores), the highest in any year for relief to victims of drought, floods and cyclones."

It may be that this is the highest figure; I do not controvert it. But what is the actual need for providing adequate relief to the drought, flood and cyclone affected people? Here I will quote the editorial comment of the *Economic Times* of 13th September 1982:

> "For the four States of the eastern zone alone, Bihar, Orissa, West Bengal and Assam the total bill for drought and floods would come to about Rs. 2,000 crores."

While according to the editorial comment of the *Economic Times*, Rs. 2,000 crores are required to meet the requirements of the drought, flood and cyclone affected people in the eastern region comprising only four States, the President's Address, expresses satisfaction that the highest amount of money has been allotted for this purpose.

SHRI CHITTA BASU: So, this does is only the Central share. The States have also to contribute their share.

MR. CHAIRMAN: His time is up. He has taken ten minutes.

SHRI CHITTA BASU: So, this does not reflect the actual situation prevailing in the country.

Then I come to the 20-Point Programme, the most tom-tommed programme, which every member from that side has been referring to umpteen times, especially the success part

[Shri Chitta Basu]

of it. I am quoting the figures supplied by the State Government upto the end of August 1982.

Sir, as regards the programme of land allotment to the landless, it is 70 per cent, Mr. Minister, of your target. In respect of Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Mr. Minister, it is only 16 per cent of your target; about rural employment it is only 28 per cent; about rehabilitation of bonded labour, it is only 27.5 per cent; about house sites allotment it is only 19.9 per cent; about slum improvement, it is only 20 per cent; about housing for economically weaker sections, it is only 24 per cent; as regards village electrification it is only 24 per cent; about bio-gas plant etc. it is only 11 per cent; for drinking water projects it is 35 per cent.

These are the figures given by the Congress(I) run State Governments. It is the compilation of figures that they have given (*Interruption*). There is no doubt about the fact that these figures are also inflated. The reality is that even a fraction of it has not been implemented. Therefore, again the President has not apprised the House or the countrymen of the real situation obtaining in our country.

Sir, again, I want to tell them that this kind of 20-point programme is not going to solve the basic problem of our country. If you want to lift the rural masses from the abysmal poverty, there should be structural changes in the society. By 'structural changes' in the society, I mean there should be radical change of income, assets and distribution, whereas the 20-point programme retains the existing exploited system and by retaining the exploited sysem you cannot lift the village masses from the morass of abysemal poverty. Therefore, Sir, the President again has not the courage to tell the truth to the country and to the House.

Sir, the President has been pleased to mention about industrial relations in our country. I would only mention some figures again to prove that his statement is not related to the actual state of affairs.

The number of mandays lost in 1981 went beyond 25 millions, i.e., 4 millions above the 1980 figure, though it was over 35 millions in 1979. The number of mandays lost in the public sector almost doubled in 1981, and in 1982 the figurt has reached, Mr. Vyas, ... (*Interruptions*).

Again, Sir, one important thing to be taken note of is, what is the number of mandays lost due to lock-out? Mr. Vyas is very much eloquent to say that it is because of the Opposition Parties, it is because of the activities of trade unions that the number of mandays lost has increased. Does he know what is the number of mandays lost due to the lock-out? Lock-out has increased......

AN HON. MEMBER: Lock-out and closure.

SHRI CHITTA BASU: Lock-out and closure, yes. But I have not included 'closure'. I am mentioning only about lock-out.

Lock-out today has become a potent weapon in the hands of employers. I will come to that later on, if you permit me. In 1978, while the number of mandays lost due to strike was 15,000, due to lock-out it was 12,000 and something. In 1979, the number of mandays lost due to strikes was 25,000 and due to lock-out it was about 8,000. In 1981, Sir, the number of mandays lost due to strike was 15,000 and odd and the number of mandays lost due to lock-out was 10,306 except in 1979 when at least 40 per cent of the mandays lost was due to the lock-out. Sir, lock-out has become a coerceive weapon in the hands of employers, and this is the actual state of affairs regarding industrial relations.

Sir, I am sorry to mention that the President has not been pleased to identify the particular reasons for the deteriorating industrial relations in

our country. I can say with all the emphasis at my command that it is because of the anti-labour policy pursued by the Government during the past one or two years that the industrial relation has deteriorated so much. Again to-day I want to warn them that if they continue to pursue this kind of policy, the industrial relation will further deteriorate and the working class of our country is not going to take your assault lying low.

The President has not really depicted the actual state of affairs in our country and, therefore, I regret I cannot sssociate myself with the Motion of Thanks.

MR. CHAIRMAN: Shri Bheravadan K. Gadhavi is not there. Shri Virdhi Chander Jain.

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो हमारे नेता श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने प्रस्तुत किया है, उसका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

मैंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अच्छी तरह से पढ़ा है । उन्होंने उसके पेज नं० 2, पैरा नं० 24 में कहा है :—

> "माननीय सदस्यगण संसार में आर्थिक और राजनैतिक संकटों के कारण जो तनाव बढ़ा है, उसका मुकाबला भारत केवल चौकसी, एकता और अपनी उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा ही कर सकता है । भ्रष्टाचार, और अकुशलता से जूझने के अलावा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मत-भेदों को इस तरह प्रकट न किया जाये जिससे हिंसा भड़के या हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो । पिछले तीन वर्षों में हम अपनी स्थिरता और प्रगति को बरकरार रख सके हैं । मेरा हार्दिक अनुरोध है कि समस्त राष्ट्र भारत की अखण्डता को बनाए रखने और उसके कल्याण तथा सम्मान को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करे ।"

यह एक विशेष पैरा है और मैं इससे विशेष तौर से प्रभावित हुआ हूं । राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंण्डता राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है अभी जो पृथकतावादी ताकतें सम्प्रदायवादी ताकतें क्षेत्रीय पार्टियां देश में पनप रही हैं, वह हमारे लिए चुनौती हैं । उनका हमें सामना करना है । इन चुनौतियों का कांग्रेस (आई) पार्टी ही सामना कर सकती है, और राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकती है हमारी पार्टी ही कर सकती है । दूसरी कोई पार्टी देश में नहीं है, जो राष्ट्रीय एकता को कायम कर सके और देश को मजबूत कर सके ।

अभी जो स्थिति पैदा हो रही है और जब क्षेत्रीय पार्टियां पनपी हैं विशेष कर दक्षिण में पनपी हैं, उनसे हमें बहुत ही चौंकस होना है और हमें अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, केन्द्र को मजबूत नहीं करेंगे तो इससे राष्ट्र को खतरा है ।

इसलिए हमें इन चुनौतियों का मुकाबला करना है । हमारे सामने बहुत चुनौतियां आ रही हैं, असम का प्रश्न है ।

असम में जब चुनाव हुए तो उसी प्रकार की चुनौती हमारे सामने आई । चुनाव जब हुए तो वहां इन प्रतिक्रियावादी पार्टियों ने, साम्प्रदायिक पार्टियों ने

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

चुनाव का बहिष्कार कर के वहां एक हिंसा को प्रोत्साहन दिया। हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले अभी भी जो कदम उठा रहे हैं, अभ। अखिल भारतीय जनता पार्टी के नेता असम के बारे में जो विचार प्रकट कर रहे थे, वह हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं और आग सुलगाने का प्रयास कर रहे हैं।

इसलिए हमें इन पार्टियों से खतरा है। यह वहां बन्द का आन्दोलन कर रही हैं और वहां हिंसा का प्रचार कर रही हैं। असम में जो डिमोक्रैटिक गवर्नमेंट का गठन हुआ है, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने जो कार्यक्रम चलाया है उसका हमें डटकर मुकाबला करना है।

दूसरा प्रश्न अकालियों की समस्या से सम्बन्धित है। हमारी प्रधान मंत्री जिस प्रकार से इस समस्या को हल कर रही हैं, जिस प्रकार से कल उन्होंने उनकी रेलिजस डिमाण्ड्स को मान लेने की घोषणा की है, उसका सारे देश ने स्वागत किया है। पंजाब ने तथा सिखों ने भी इसका स्वागत किया है। उनकी रेलिजस डिमाण्ड्स वाजिव थीं और उनको मान लेने की घोषणा समय पर की गई है। परन्तु जो उनकी राजनीतिक डिमाण्ड्स है वह इस प्रकार की हैं कि वे एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त के मुकाबले में संघर्ष कराना चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारा राजस्थान पांच वर्षों से भयंकर अकाल की स्थिति से गुजर रहा है। जो रावी-ब्यास समझौता हुआ था उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया था कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी पहुंचाना है। उसको सिंचित करना है। यदि 5–6 वर्षों में राजस्थान कैनाल का निर्माण हो जाता तो राजस्थान को बड़ी प्रगति होती और राजस्थान भी दूसरे प्रान्तों की तरह विकसित हो जाता। परन्तु देरी से काम किया गया। 1955 में जो समझौता हुआ था उसके कारण राष्ट्र ने पाकिस्तान को भी 110 करोड़ रुपया दिया ताकि हमारे यहां रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी पहुंच सके। जब पंजाब में अकालियों की ही सरकार थी, उन्होंने उस समय उस समझौते के बारे में कोई बात नहीं उठाई परन्तु अब इतने वर्षों के बाद उस प्रश्न को खोलने की स्थिति पैदा की है जोकि किसी प्रकार से सही नहीं है। अभी भी रोपड़ और फ़ीरोज़पुर हेडवर्क्स पंजाब सरकार के कण्ट्रोल में हैं। हम चाहते हैं कि वह भारत सरकार के कण्ट्रोल में रहें। भाखड़ा नियन्त्रण बोर्ड के कण्ट्रोल में रहे। यह निर्णय तो हो चुके हैं और अब इसका कार्यान्वियन भी होना चाहिए। पंजाब में कांग्रेसी गवर्नमेंट होने के बावजूद जब राजस्थान कैनाल में पानी की आवश्यकता होती है तब पानी नहीं मिलता है जिसके कारण वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं। हर साल ऐसी स्थिति पैदा होती है इसलिए यह आवश्यक है कि हेडवर्क्स भारत सरकार के नियन्त्रण में रहें।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, इस देश में पांच करोड़ लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की समस्या का दूर करने के लिए जो कदम सरकार ने उठाए हैं, वह भी सराहनीय हैं। जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है या जो एन आर ई पी तथा अन्य प्रोग्राम हैं उनको यदि भली भांति क्रियान्वित किया जाए तो हमारा देश विकास कर सकता है। छटी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से नीचे 150 लाख परिवारों, अर्थात् $7\frac{1}{2}$ करोड़ लोगों को ऊपर लाने का कार्यक्रम बनाया गया

है, हम चाहते हैं इसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। मैंने राजस्थान में गांव-गांव जाकर देखने का प्रयास किया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस प्रकार से क्रियान्वित हो रहा है तो मैंने देखा—मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस कार्यक्रम का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अनुदान की राशि सही रूप में गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती है। छोट परिवारों को नहीं मिलती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन कार्मशियल बैंक उसमें से अपना हिस्सा ले लेता है, विकास अधिकारी अपना हिस्सा ले लेता है और प्रभावशाली सरपंच अपना हिस्सा ले लेता है वहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए सारे संसद् सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों को सावधान हो जाना चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। 7,50 करोड़ रुपया सैण्ट्रल गवर्नमेंट से और 7,50 करोड़ रु० प्रान्तीय सरकार से और 3,000 करोड़ रुपया और बैंकों से यानि 4,500 करोड़ रुपया ऋण और अनुदान से मिलेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी संसद् सदस्यों को पूरी तरह से दिलचस्पी लेनी चाहिए। इसी प्रकार एन० आर० ई० पी० के कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। फूड का जितना शेयर हमें मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मुझे दुःख के साथ कहना पढ़ रहा है कि ड्राउट-प्रान-एरियाज़ के विकास के के लिए डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम है, उसको समाप्त कर दिया गया है, जबकि बाड़मेर और जैसलमेर क्षत्र सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित है। यह काम भी आपने श्री एम० एस० स्वामिनाथन की रिपोर्ट के आधार पर किया है। यह भी पता लगा है कि इस कार्यक्रम को आपने डजर्ट डवेलपमेंट प्रोग्राम में मिला दिया है। हमारी मांग है कि उसकी राशि का बढ़ाया जाना चाहिए। हिली एरियाज के डेवलपमेंट के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 170 करोड़ रु० जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में थे, की जगह पर आपने 560 करोड़ रुपए कर दिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डैजर्ट डवेलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपये के स्थान पर आपको 500 करोड़ रुपये रखने चाहिए, जिससे वहां पर वनों का विकास हो सके। जिस प्रकार आप हिली एरियाज़ का प्राथमिकता दे रहे हैं, असम और दूसरे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसी प्रकार आपको उत्तर पश्चिम भारत का जो सीमावर्ति रेगिस्तान क्षेत्र है, उस को भी नहीं भूलना चाहिए।

मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जिसको मेने बार-बार यहां पर कहा है। हमारा 50 प्रतिशत भाग आज तक भी आल इंडिया रेडियो की आवाज को नहीं सुन पाता है। उन जगहों पर पाकिस्तान के रेडियो की आवाज आती है, जिस का वहां पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। लेकिन आप टी० वी० की ओर बढ़ रहे हैं, कलर टी० वी० की ओर बढ़ रहे हैं। जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको आप नहीं दे रहे हैं। चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आपने पैसे की कमी कर उस कार्यक्रम की अवहेलना की। मैं यह कहना चाहता हूं, चूंकि अब काम्यूनिकेशन वर्ष चल रहा है, आपको कम से कम इस ओर ध्यान दे कर उन क्षेत्रों में कम से कम रेडियो की व्यवस्था करनी चाहिए।

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जिस प्रकार डाकुओं की समस्याओं को हल किया जा रहा है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, वह बहुत ही घातक है। डाकुओं का आत्मसमर्पण कराकर उनका सम्मान किया जा रहा है। अभी मलखान सिंह और फूलनदेवी का स्वागत किया गया। दूसरी ओर पत्रकार उनके स्टेटमेंट और इण्टरव्यूह ले रहे हैं। जिस प्रकार उनको प्रतिष्ठा बढ़ रही है, यह हमारी पालिसी के खिलाफ है। जिन्होंने इतने कत्ल किए हैं, चरित्रहीन कार्य किए हैं, उन लोगों का इस प्रकार से बढ़ावा देना, हमारी पालिसी के खिलाफ हैं। यह हमारी नीति के खिलाफ है। इस लिए इस कार्यक्रम के बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए और हमें इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिस से कि हमारी इमेज बढ़, हमारी शक्ति बढ़े, और राष्ट्र की इज्जत बढ़े।

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद): माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस दल का सदस्य होने के नाते ही नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जरिए देश को जो नई दिशा दी है उस से देश का बहुत भला होने वाला है। मैं इस अवसर पर मुख्य रूप से दो-तीन बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 50 हजार उचित-दर की दुकानें खोली गई हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है तथा उसे अधिक कुशल बनाया गया है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उद्देश्य सही है लेकिन वितरण प्रणाली नीचे के स्तर पर सही नहीं है। जो सरकार का उद्देश्य है—उस उद्देश्य के अनुसार गरीबों को न गांवों में और न शहरों में सही समय पर और सही ढंग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गल्ला मिलता है या चीनी मिलती है। हालांकि यह विषय राज्य सरकारों के अधीन है, लेकिन केन्द्रीय शासन को भी देखना चाहिए कि वितरण सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस सभा के माध्यम से मैं केन्द्रीय शासन से कहना चाहता हूं—वे एक-एक ज़िले को सैम्पिल बना कर देखें कि वहां पर वितरण प्रणाली सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। मैं अपने जनपद इलाहाबाद की बात जानता हूं—वहां पर वितरण प्रणाली बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, सही ढंग से लोगों का गल्ला नहीं मिल रहा है, दुकानों पर गल्ला सही समय पर नहीं आता है और जो आता है वह उच्च-कोटि का नहीं होता है, निम्न-कोटि का होता है और लोगों को उचित मूल्य पर भी नहीं मिलता है। सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

इस अभिभाषण में सूखे और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 700 करोड़ रुपये की धनराशि देने की बात कही गई है। मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश को जो जनसंख्या के हिसाब से, सूखे और बाढ़ से प्रभावित होने के हिसाब से, देश का सब से बड़ा राज्य है, उस को सूखे की

सहायता के मद में केन्द्र से कोई धन नहीं मिला है। मैं यह मानता हूं कि इसमें केन्द्र का दोष नहीं है उत्तर प्रदेश शासन ने शायद समय पर धन की मांग नहीं की, लेकिन उस गलती के बावजूद भी मैं इस सभा के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को सूखे और बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, भले ही उन की मांग देर से आई हो या उन्होंने मांग न भी भेजी हो, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए जैसे अन्य राज्यों का सूखे और बाढ़ में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी गई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को भी मिलनी चाहिए।

गेहूं और धान की वसूली के सम्बन्ध में कहा गया है कि वसूली पर किसानों को उचित मूल्य मिलता है। इस के बारे में, मान्यवर, मेरा बहुत कटु अनुभव है। जब किसान की फसल खलिहान में आती है, जब वह उस को बेचना चाहता है—उस समय सरकार की तरफ से राज्यों में उचित दाम पर खरीदने को दुकानें नहीं मिलती हैं तथा विवश हो कर किसानों को अपने गेहूं और धान को कम दामों पर व्यापारियों को बेचना पड़ता है। किसानों को चूंकि सरकार को हर तरह की अदायगी करनी होती है, इस लिए बाध्य हो कर उसे कम दामों पर बेचना पड़ता है। मेरा केन्द्रीय शासन से अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों को आदेश दे कि जिस समय रबी और खरीफ़ की फसल आये उस के पहले ही सरकार द्वारा तय मूल्यों पर गल्ला और धान को खरीदने को दुकानें खोली जांय।

15.05 hrs.

[DR. RAJINDRA KUMAR BAJPAI *in the Chair*].

मान्यवर, अभी जब आन्ध्र का चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव में जाने का मुझे मौका मिला था। वहां शासन द्वारा कपास की कीमत 550 रुपये प्रति क्वींटल मुकर्रर की गई थी लेकिन वहां पर 450 रुपये प्रति क्वींटल पर किसान कपास को बेचने पर बाध्य हो रहे थे क्योंकि सरकार की तरफ से कपास खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के बारे में है। देहातों में इसका भी सही उपयोग नहीं पा रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि विभाग के लोग ज्यादातर फर्जी मास्टर रोल दिखा देते हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखा है कि "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष 33 करोड़ से अधिक अतिरिक्त श्रम-दिवसों का देहाती रोजगार पैदा किया जाएगा"। मेरा कहना यह है कि उतना प्रावधान नहीं किया गया है और अगर इस की जांच की गई तो बहुत ज्यादा फर्जी काम पाया जाएगा। मैं यह चाहूंगा कि इस की जांच की जाए और हर राज्य में एक एक जिले को सैम्पुल के रूप में लेकर कितना काम मास्टर रोल पर हुआ है, और कितना सही काम हुआ है और गलत काम हुआ है, कितना यह देखा जाए और गलत काम करने वालों को दंडित किया जाए। यह मामला राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, यह सही है लेकिन क्योंकि केन्द्रिय सरकार सहायता देती है और फिर राज्य सरकारें इस को चलाती हैं, इसलिए जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार इस चीज को देखे।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि विशेष कम्पोनेन्ट प्लान और अनुसूचित जातियों के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं, उन का फायदा नीचे स्तर के लोगों को नहीं मिल रहा है। केन्द्रीय सरकार की जो इच्छा है और हमारे नेताओं की जो इच्छा है

[श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी]

और जिस भावना को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में व्यक्त किया है उस की अभिव्यक्ति गांवों में नहीं हो रही है। जो पैसा खर्च हो रहा है, उस का दुरुपयोग हो रहा है और इसका करनी पड़ेगी। उद्देश्य सही है, लेकिन वह पूरा नहीं हो रहा है।

परिवार नियोजन के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। विरोधी पक्ष के नेता श्री जेठमलानी ने अपने भाषण के बीच में परिवार नियोजन के मामले में स्व. संजय गांधी की तारीफ की थी लेकिन जिस समय वह परिवार नियोजन चल रहा था तो विरोधी पक्ष के लोगों ने बड़ा हो-हल्ला मचाया था और कहा था कि गलत तरीके से नसबन्दी की जा रही है। . . . (व्यवधान) . . . .यह भी कहा गया था कि जिन लोगों की गलत नसबन्दी की गई है, जनता पार्टी का शासन आने के बाद उन को 10 हजार रु० मुआवजा देगें। केन्द्र और राज्यों में जनता पार्टी ने 28 महीनों तक शासन किया लेकिन एक भी केस ऐसा गलत नसबन्दी का नहीं पाया, जिस को 10 हजार रु० मुआवजा देते जैसा कि इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में कहा था। विरोधी पक्ष ने उस समय परिवार नियोजन को जितना नुकसान पहुंचाया उतना शायद इस देश में किसी ने नहीं पहुंचाया। मुझे अभी चीन जाने का मौका मिला था। मैं चीन में परिवार नियोजन की तारीफ करना चाहता हूं। चीन ने परिवार नियोजन के मामले में ईमानदारी और सख्ती के बूते पर काफी अंकुश लगा दिया है और परिवार नियोजन को एक सिद्धान्त के रुप में वहां की सरकार ने माना है। वहां पर कुछ दंडित करने का प्रावधान नहीं है लेकिन जो लोग परिवार नियोजन को अपनाते हैं और चीन की सरकार की नीति को मानते हैं, उनको सुविधाएं देने की बात वहां पर है। मैं भी इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिएं कि वह दंडित न करे लेकिन अगर एक परिवार दो सन्तानें पैदा करता है, तो उस को कुछ सुविधाएं देने की बात हो और जो परिवार दो सन्तानों से ज्यादा पैदा करता है, उसको दंडित तो न किया जाय लेकिन उन सुविधाओं से उनको वंचित किया जाए जो दो सन्तान पैदा करने वाले को मिलती हैं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहा गया है कि "हमारी दूरदर्शन नीति में देहाती लोगों की जरूरतों, और शिक्षा तथा विकास के लिए इस शक्तिशाली माध्यम के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभापति जी, आप उस स्थान में से आती हैं। इलाहाबाद को पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण रहा है और आजादी की लड़ाई इलाहाबाद से संचालित हो रही थी। धार्मिक दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उसका बड़ा महत्व है। शिक्षा की दृष्टि से मध्य में होने की दृष्टि से इलाहाबाद में मैं समझता हूं कि सर्वोपरि नहीं है तो किसी दूसरे इलाके से कम भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इलाहाबाद आज दूरदर्शन के मैप पर नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चचाहता हूं कि इलाहाबाद को अविलंब दूरदर्शन के मैप पर लाया जाए। वहां पर पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ का माइक्रोवेव लिंक उपलब्ध है जिससे थोड़े खर्चे में टेलीविजन का प्रावधान किया जा सकता है। जब देवरिया और दूसरे छोटे जिले इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं तो इलाहाबाद में दूरदर्शन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

उद्योग के बारे में इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ इलाके में सब लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे अच्छा और दुनिया का दूसरे नंबर का सिलिकासेंड निकलता है और यहां पर दस हजार मजदूर करते हैं। लेकिन इस सिलिकासेंड से जो शीशा बनता है वह दूसरे प्रदेशों में बनता है। इसकी यहां से ढुलाई होती हैं, इससे शीशा महंगा पड़ता है। यहां पर ब्राडगेज लाइन है, बिजली है, सड़क है और 10 हजार मजदूर काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस इलाके में शीशा बनाने का कारखाना अविलंब खोला जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को रोजी-रोटी और काम मिल सके।

अंत में मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। आज आसाम में जो आंदोलन हो रहा है, पंजाब में जो थोड़ा बहुत आंदोलन हो रहा है, उसके बारे में मैं विरोधी दलों के लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इनकी कथनी और करनी कहीं भी एक नहीं है। जब ये गांवों में जाते हैं तो किसानों को कहते हैं कि गेहूं का दाम बढ़ना चाहिए, गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए, कपास का दाम बढ़ना चाहिए, धान का दाम बढ़ना चाहिए, लेकिन जब शहरों में आते हैं तो भाषण करते हैं कि गेहूं सस्ती मिलनी चाहिए, चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, चावल सस्ता मिलना चाहिए। जब आसाम जाते हैं तो वहां लोगों से कहते हैं कि आंदोलन करना चाहिए और जब खून-खराबा होता है, जिसके जिम्मेदार वे आंदोलनकारी हैं, लेकिन उसका आरोप केन्द्रीय सरकार पर लगाते हैं। कहते हैं कि चुनाव कराने के कारण यह हुआ है। एक तरफ कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन न बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ आसाम में उसके पक्षधर बनते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था न करके राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाए। नौकरशाहों के हाथों में हुकमत रहे। इस संबंध में मैं केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आसाम में चुनाव कराके उसने लोकतंत्रीय मल्यों को कायम किया है और किसी आंदोलन को चुनाव टालने के लिए सफल नहीं होने दिया। नहीं तो कल यह भी हो सकता है कि लोक सभा के चुनाव भी न होने दिए जाएं, अन्य राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव भी न होने दिए जाएं इस प्रवृत्ति को बढ़ावा न देकर केन्द्र सरकार ने जो काम किया है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और खाद का उपयोग कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि खाद बहुत महंगा है, जिसको किसान खेतों में डालने में असमर्थ है। दूसरी तरफ सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो यह भी सही नहीं है। एक नलकूप से 250 एकड़ भूमि सिंचित दिखाई जाति है। जबकि असलियत यह है कि अगर चौबीसों घंटे बिजली मिले तब भी 250 एकड़ जमीन सिंचित नहीं हो सकती।

नहर का जितना कमान्ड एरिया दिखाया जाता है, उतना कमान्ड एरिया वह नहीं होता है। कोई भी नहर उतनी जमीन को नहीं सींचती। खाद का दाम भी ज्यादा है। कृषि मंत्री जी ने "इपको" के एक सम्मेलन में कुछ दिन पहले भाषण देते हुए कहा :—

"The survey concedes that despite an additional 9 million hectares under Irrigation and higher use of fertilizers by 2 million tonnes between 1978-79 to 1982-83, there has not

[श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी]

been significant increase in the level of production of food-grains."

इसका कारण यही है कि खाद की कीमत केन्द्रीय सरकार को कम करनी चाहिए। विरोधी दल के लोग जनता में जाकर जो कुछ कहें। लेकिन, केन्द्रीय सरकार किसानों को जिस दर पर खाद दे रही है, उस दर पर देने के बाद भी केन्द्रीय सरकार को 5 अरब रुपए का घाटा उठाना पड़ता है। लेकिन किसानों के हित में, देश में गल्ला बढ़ाने के हित में केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि खाद का दाम कुछ और कम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री टी० ए च० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के विचार सुने। अपने-अपने विचार बड़ी खूबी से लोगों ने रखे। उपलब्धियों के बड़े-बड़े ढोल पीटे गए। सही उपलब्धि मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जवाब भी जानना चाहूंगा। समय कम होने के कारण पाइन्ट्स ही बोलना चाहता हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि सरकार वाकई क्या कर रही है। क्या यह सही नहीं है कि इस सरकार के कार्यकाल में हिंसक वारदातें बढ़ीं और सरकार के जमाने में औरतों पर बलात्कार बढ़े हैं। दलितों पर अत्याचार हुए हैं।...... (व्यवधान) क्या यह भी सही नहीं है कि सामाजिक मतभेद और दंगे-फसाद बढ़े हैं। दो दिन में तीन दंगे हुए हैं। यह सरकार के आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। विघटन की जो ताकतें हैं, उनको भी बढ़ावा मिला है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की जो अर्थ नीति अंतर्राष्ट्रीय थैली शाहों एवम् देश के पूंजीपतियों की मिली-भगत से हमारा राजतन्त्र आम लोगों के शोषण का हथियार बन चुका है। गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती चली जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। काले धन की अर्थव्यवस्था में जहां बड़े इजारेदार घरानों के मुनाफे आसमान को छू रहे हैं वहां आम आदमी की क्रय शक्ति बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी है। निरंकुश अर्थव्यवस्था तथा लूट नीतियों से न केवल नियोजन में भटकाव और खोखलापन आ चुका है बल्कि रोजगार के अवसर भी क्रमशः बंद होते जा रहे हैं। सरकार की आर्थिक नीतियों ने एक ऐसे बिचोलिए वर्ग को जन्म दिया है, जिसकी वजह से जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट के लक्षण साफ नजर आते हैं। बिचोलियों की वजह से जहां उत्पादकों को अपनी मेहनत का मुनाफा नहीं मिल पाता वहीं उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतें चुकानी पड़ती हैं। मुजफ्फरनगर से 25 रुपए क्विंटल गोभी दिल्ली में आती है। लेकिन दिल्ली के बाजार में डेढ़-सौ और दो-सौ रुपए प्रति क्विंटल बिकती है। यह बीच का जो इतना मार्जिन है, कौन खा रहा है? इस पर सरकार क्यों प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती? सरकार इसका जवाब दे। उत्पादनकर्ताओं के साथ दोहरा शोषण हो रहा है। खाद, बिजली, मशीन, दवाई आदि के लिए कमर तोड़ कीमतें चुकानी पड़ती हैं और इस तरह प्रति वर्ष औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से 5,000 करोड़ रु० का मुनाफा उठाता है। लेकिन सरकार कृषि को उद्योग मानने को तैयार नहीं है। तो यह ज्यादती किसानों पर क्यों है जबकि किसानों के गन्ने के 4,300 करोड़ रु०

सरकार दिला नहीं पा रही है। स्वयं सरकार दाम बढ़ा रही है, टैक्स लगा रही है। इसका क्या मतलब है? गरीब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है यह सरकार की नीति है।

इस मुल्क में हमने हमेशा यह मांग की थी सरकार से कि निर्यात बढ़े। लेकिन निर्यात के बजाय आजकल आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। कारण यह है कि आयात में कमीशन मिलता है, इसलिए उसको बढ़ाया जाता है ताकि सरकारी पक्ष की जेबें गरम हों, काला धन बढ़े और चुनाव में हमारे ऊपर अत्याचार हो, जबरदस्ती वोट लिये जायें और इस ढंग से जनतंत्र का गला घोंटा जाय।

गेहूं आयात किया जाता है, और जो सरकारी गोदाम हैं वहां इतनी कुव्यवस्था है कि प्रति वर्ष 60 लाख टन अनाज बरबाद होता है और गेहूं फिर बाहर से मंगाया जाता है। तो क्या सरकार अपने गोदाम ठीक नहीं कर सकती? किसान की खेती में बड़ी-बड़ी बीमारियां लग रही हैं। आपने अनुसंधानशालाएं खोल रखी हैं जिन में वैज्ञानिकों पर 100 करोड़ रु० हर साल खर्च होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या काम कर रही हैं? फसलों की बीमारियों की रोक-थाम क्यों नहीं होती ताकि किसान की फसलें बरबाद न हों?

मजदूरों की क्या हालत है यह आप बम्बई में चल रही हड़ताल से देख लीजिए। 14 महीने हो गए हड़ताल को लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हो सकी। अगर वह सरकार से उचित मांग भी करते हैं तो गोली मिलती है। यह तो गोली और डंडे की सरकार है। कोई कह रहा था यह तो बहुत अच्छी सरकार है, सारी मांगें पूरी कर दीं। खाने के लिए गोली, पहनने के लिए कफ़न और रहने के लिए कब्रिस्तान। यही सरकार कर रही है। गन्ने से सरकार पावर अल्कोहल बना सकती है। पैट्रोल में मिला कर उसका इस्तेमाल हो सकता है। क्यों नहीं सरकार इस मुल्क में पावर अल्को-हल पैदा करती ताकि पैट्रोल का आयात कम हो, यहां की पूर्ति के लिए पैट्रोल काम आये और इस प्रकार विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। इस तरह से गन्ना उत्पादकों को भी उचित मूल्य मिल सकेगा।

पिछड़े क्षेत्रों के बारे में अभी हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य कह रहे थे। मैं बताना चाहता हूं इस सरकार का क्या रवैया है? पहाड़ों की तरक्की के सम्बन्ध में जो वहां की प्रगति के काम थे, नियोजन के काम थे वह सरकार के गलत निर्णयों के कारण रुक गये हैं जिससे वहां लोगों की तरक्की नहीं हो सकती। 1980 में इंडियन फ़ोरेस्ट ऐक्ट में जो संशोधन हुआ उससे यह हुआ है। मैं यहां उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूं कि 3/4 साल पहले जो योजनायें प्लान में मंजूर थीं जिनके ठेके हो चुके हैं, उन पर काम चालू नहीं हुआ इस इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में संशोधन की वजह से, जिसके कारण विभाग फ़ोरेस्ट के अन्दर से सड़क नहीं ले जा सकते, नहर बिजली के तार नहीं जा सकते। तो तरक्की कैसे होगी, मैंने सुझाव दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और भारत के वन मंत्री को, लेकिन वह सुनने और समझने से इन्कार करते हैं। जो संशोधन हो गया है उसे बदलना नहीं चाहते क्योंकि जो हमारी डिक्टेटर साहिबा हैं, उनसे वह डरते हैं। उन्होंने जो पास कर दिया और जो कानून बन गया, उसके खिलाफ वह बोल नहीं सकते, सुझाव नहीं दे सकते, तो यह सरकार क्या काम करेगी?

[श्री टा० एस० नेगी]

मैंने सुझाव रखा था कि जितने काम प्लान में हैं, उनको चालू किया जाये। जो तीन विभाग सम्बन्धित हैं एक तो राजस्व का, दूसरा फारेस्ट और तीसरे जिस विभाग का निर्माण कार्य हो रहा हो, उनका एक एक अफसर बैठ जाये और काम शुरू करवा देवें। स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजें या गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजें। स्वीकृति बाद में आ सकती है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा बता दूं कि रेड्डी साहब का और गिरी साहब का जो चुनाव हुआ था, वैसा ही चुनाव मेरा भी था। मेरे खिलाफ, राजा के लड़के को खड़ा किया था। मेरे बारे में यह कह दिया कि यह तो बहुगुणा का उम्मीदवार है। (व्यवधान) बहुगुणा जो 118 सीटों पर चुनाव भाषण करने गए थे। उनमें 98 उम्मीदवार जीत कर आये। आप रिज़ाइन कीजिए, हम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुगुणा के उम्मीदवार हैं . . .

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए।

श्री टा० एस० नगी : फिर भी मैं राजा के लड़के की जमानत ज़प्त करा के यहां आ गया हूं। अच्छा हुआ, बात क्लीयर हो गई।

(व्यवधान)

मैंने आपसे निवेदन किया कि पहाड़ियों की प्रगति अवरुद्ध हो चुकी है, इसके लिए सरकार का कुछ कदम उठाने चाहियें। मैंने सुझाव दिया था कि केन्द्र के फारेस्ट मंत्री से मिलने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रधान मंत्री से मिलिए। उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधि सीधे प्रधान मंत्री से मिले और इसमें जो ठीक हो सकता है; वह करायें। इस सम्बन्ध में मैंने पत्र भी लिखा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है।

डी० जी० वी० आर० के मजदूर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। उन पर दोहरी नीति लागू होती है। काम करने के लिए डिसिप्लिन के लिए मिलेटरी एक्ट उन पर लागू होता है और जो तनख्वाह तथा भत्ता उनको मिलता है, उसके लिए सिविलियन एक्ट लागू होता है। यह दोहरी नीति क्यों है? इसको समाप्त करना चाहिए। उनको एक तरफ कर दें, चाहे मिलिट्री कानून के अण्डर कर दें या सिविलियन के अण्डर कर दें। यह मेरा निवेदन है।

एशियाड के बारे में बड़ी बातें हुई हैं। एशियाड के जमाने में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के एक माननीय सदस्य का पत्र हमारे पास भी आया उन्होंने कहा कि टिकट तो ब्लैक में पहले ही बिक चुके थे। लोगों को टिकट नहीं मिला। जब एशियाड शुरू हुआ तो जब तक मिलिट्री के अन्तर्गत उनका प्रशासन था वह ठीक रहा और सुरक्षा रही लेकिन कांग्रेसियों की धांधलबाजी उन्होंने चलने नहीं दी। इसलिए उनको हटाया गया और वहां का प्रशासन पुलिस को दे दिया गया। फिर जितने चाहो जाओ। ये लोग आते-जाते रहे, कोई कानून इसके लिए नहीं था।

एशियाड के खाने के बारे में अगर चर्चा होगी तो पता चलेगा कि जिस तादाद में लोग बाहरी मुल्कों से आये उससे तीन-चार गुना खाना वहां खाया जाता

रहा है । मैं समझता हूं कि ये कांग्रेसी खा गये । यह बातें वहां हुई हैं । जब यह चर्चा सदन में होगा तो सारी बात साफ हो जायेगी ।

हमारे हिन्दुस्तान में जो सोना था, वह भी विदेशी ले गये । हमें सोना भी नहीं मिला, कम्पीटीशन में जीते भी नहीं । हमारा इतना बड़ा मुल्क जो चीन के बाद दूसरा है, उसको कुछ भी पुरस्कार नहीं मिला, हमें बहुत कम गोल्ड मैडल मिले । हम एक दो ही ले पाये हैं ।

असम की भी यहां चर्चा हुई । उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि कांस्टीट्यूशनल ग्रौब्लीगेशन पूरा करने के लिए चुनाव वहां पर हुए हैं । क्या मुझे यह जानने का हक है कि जो 6, 7 लाख वोटर लिस्ट में ग्राने थे, उनको क्यों नहीं लिया गया ? उनका नाम इलैक्टोरल लिस्ट में क्यों नहीं लिया गया ? इसका जवाब दिया जाना चाहिए । मनमानी ग्रौर धाँधलेबाजी इस सम्बन्ध में की गई है, मेरे ख्याल में इससे कांस्टीट्यूशनल ग्रौब्लीगेशन पूरा नहीं होगा । मेरा कहना यह है कि जो चुनाव वहां हुए हैं, वह जल्दी समाप्त हो जायेंगे ग्रौर यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है । यह ग्राप जान लें ।

भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है कि मिनिस्ट्रीज में कार्य करवाने के जाने के सम्बन्ध में ग्राम लोग ग्रापस में कहते हैं कि यह ब्रीफकेस सरकार है, पसा ले जाइये ग्रौर काम करवाइये । ब्रीफ केस ही नहीं, इस किस्म के जितने भी बुरे काम हो सकते हैं वह बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में हो रहे हैं । यह दुकानें खुली हुई हैं, सरकारी दफ्तर नहीं हैं, वहां पर सौदेबाजी होती है ।

SHRI G. M. BANATWALLA: Mr Chairman, I can understand the point he is making, but referring to all the Ministers and saying that they are dishonest that is too much. Of course, he can make his points. It would be rather an unparliamentary way of putting things, and it should be expunged.

सभापति महोदय : मैं देख लूंगी । ग्रगर कुछ ग्रनपार्लमेन्टरी होगा तो एक्सपंज कर दिया जायेगा ।

ग्रब ग्राप जल्दी खत्म करिए, ग्रापका टाइम हो गया है ।

श्री टी० ए० नेग : मैं साबित कर सकता हूं कि कहां कहां क्या हो रहा है । कहां पर क्या भ्रष्टाचार है । ग्रभी ग्रभी दिल्ली में एलेक्शन हुए थे । मैं ग्रापको क्या बताऊं कि कितना भ्रष्टाचार हुग्रा ग्रौर कितने गलत काम हुए ।

सभापति महोदय : ग्रापको नोटिस देना चाहिए । कोई एलिगेशन लगाने से पहले प्रूफ देना होता है ।

श्री टी० ए० नेग : जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए ग्रौर उसमें हमारी मदद लेनी चाहिए । हम ग्रापको बतायेंगे कि कैसे कैसे काम हो रहे हैं । ग्रभी दिल्ली में चुने गये चार पांच लोगों ने क्या क्या कृत्य किए ?

**ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं ग्रगर उनके बारे में यहां नहीं बोला जायेगा तो ग्रौर कहां बोला जायेगा । सच्चाई क्या है वह ग्रगर हम जनता के सामने बतलायगे तो पता चल जायेगा कि ग्राप इस मुल्क को कहां लिए जा रहे हैं ग्रौर क्या काम कर रहे हैं ।

---

the record straight.

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज): सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने 18 फरवरी को संवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। मैं तीन चार रोज़ से दोनों तरफ के सदस्यों का यहां पर सुन रहा हूं। मैंने सी०पी०एम० के नेता को सुना, जेठमलानी जी को सुना, सुब्रह्मण्यमस्वामी जी को सुना और अभी वसु जी को भी सुना। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को शुरू में ही देखें तो उन्होंने इसी से शुरुआत ही की है कि हमारा देश इस समय चुनौतियों से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने कहा है कि आर्थिक व्यवस्था में हमें सुधार लाना है और जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको काबू में लाना है। और जैसी कि परम्परा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल दो चीजों का ही जिक्र होता है--एक तो पिछले वर्ष की क्या उपलब्धियां रही हैं और अगले वर्ष क्या दिशा होगा, उसका संकेत रहता है। आप देखें तो 25 में मे 17 पैराग्राफ़ों में संक्षेप में उपलब्धियों की ही चर्चा की गई है। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि मुद्रास्फीति पर काबू पाई गई है और अब वह केवल 2.8 प्रतिशत ही रह गई है? सुब्रह्मण्यमस्वामी जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार गलत बात कहती है, वह कहती है कि थोक कीमतों पर कण्ट्रोल किया है लेकिन दूसरी तरफ फूड की कीमतों पर काबू नहीं पाई है। आप वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। यदि आप भारत के नक्शे को देखें, तो पायेंगे कि 21 करोड़ दो लाख इन्सान, अभी जो साइक्लोन आया है उसको छोड़ कर, सूखे से प्रभावित हैं। क्या वे वास्तविकता को भूल जाते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों में भी हमने इसका सामना किया और जितनी हमारी दुकानें थी, उसके अतिरिक्त 50 हज़ार दुकानें और खोली हैं। इस प्रकार हमने कीमतों पर काबू पाने का प्रयास किया और जो फुटकर कीमत बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसको हमें ध्यान में रख कर ही बात करनी चाहिए। इसके अलावा हमने उद्योगों के बुनियादी ढांचे में भी परिवर्तन किया है। जिस प्रकार की स्थिति जनता पार्टी अपने शासन काल में छोड़ गई थी, उसको हमने पिछले तीन सालों में काफी सुधारने का प्रयास किया है। रेलवें में फ्रेट में सुधार किया है, बिजली में सुधार किया है, कोयले के उत्पादन में 4.2 प्रतिशत का सुधार किया है, फर्टिलाइजर में 9.6 परसेंट, ढुलाई में 3.7 परसेंट का सुधार किया है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या, कच्चे तेल जिस पर हमें फारेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है, उसमें हमने 30 परसेंट से भी ऊपर उपलब्धि की है। इसी प्रकार निर्यात में भी 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। जहां दुनिया के लोग अपने देश की अर्थ व्यवस्था को काबू करने के लिए इन्वेस्टमेंट में कमी कर रहे हैं, वहीं पर इस सरकार ने पिछले तीन सालों में इन्वैस्टमेंट बढ़ा दिया है। इस साल के भी बजट में हमने 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उपलब्धि नहीं है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी, को माननीय प्रधान मंत्री जी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था, उनकी भी पेंशन को बढ़ाया है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप बहुत पुरानी बात कह रहे हैं। मैं भी एक स्वतन्त्रता सेनानी हूं।

श्री राम प्यारे पनिका : इस सरकार ने अनुसूचित जाति और जन-जातियों पिछड़ी जातियों के लिए तथा पहली बार हमारे हिन्दुस्तान के जो पिछड़े हुए मांझी हैं, उनके लिए भी एक बीमा की योजना बनाई है। ट्राइल सब-प्लान में दस करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे सरकार की दिशा दिखाई पड़ती है। हमने कहीं भी तथ्यों को छिपाया नहीं है और न छिपाने का प्रयास ही किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिए हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान के दलितों और हरिजनों—आदिवासियों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है, लेकिन ये लोग उसकी आलोचना ही करते रहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : सब को उजाड़ा जा रहा है।

श्री राम प्यारे पनिका : शास्त्री जी, आप मुझे बोलने दीजिए। क्यों आपके लीडर ने कहा है—गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड इल्यूजन, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता है।

सभापति महोदया, अभी हमारे एक साथी रामचरित मानस का उदाहरण दे रहे थे। यह बात सही है कि यत्रतत्र राज्यों में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको अब नया रूप दिया है, जिससे हमारे देश का कल्याण होगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमने शिक्षा में भी सुधार किया है, पीने के पानी की ओर भी ध्यान दिया है। मैं राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उन्होंने अभी अभिभाषण में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी ज़िक्र किया है। उन्होंने ईराक और ईरान की समस्या को उठाया है, उन्होंने ईजराइलियों द्वारा फिलस्तीनियों पर जो अत्याचार हुए हैं उन का उल्लेख किया है, उन्होंने सारी दुनिया के देशों से कहा है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम शान्ति स्थापना के लिए एक होकर रहे। इतना ही नहीं, आज हिन्दुस्तान के अन्दर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना होने जा रही है—हमारे यहां दुनिया के तमाम नान-एलाण्ड देशों का सम्मेलन हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में होने जा रहा है। आज दुनिया के देशों में इस बात का कम्पीटीशन होने लगा है, कोशिश होने लगी है कि वे इन्दिरा जी की सहानुभूति प्राप्त करें। आप जानते हैं पिछले दिनों हमारे देश में अनेक देशों के राजनेता आये तथा इन्दिरा जी और राष्ट्रपति जी भी दूसरे देशों की सद्भाव यात्रा पर गये। इतना ही नहीं, थोड़े दिनों बाद कामनवेल्थ देशों का सम्मेलन भी हमारे यहां होने वाला है। यह सब भारत की विदेश नीति की सफलता का सूचक है। हमारी नान-एलाइण्ड पालिसी ने दुनिया के देशों में सद्भाव की भावना जगाई है।

क्या इन सब से देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है? आज हमारे विरोधी दलों के लोग कह रहे थे कि हमारी फारन पालिसी ऐसी है जिस से हम दुनिया में अलग-थलग पड़ गये हैं। मैं अपने विरोधी दलों के सदस्यों से पूछता हूं—क्या यह अलग-थलग होने का प्रमाण है कि दुनिया के 100 देशों ने हम से अपील की कि गुट निर्पेक्ष सम्मेलन हमारे देश में हो, यह उन के विश्वास का प्रतीक है कि यह सम्मेलन इस देश में होने जा रहा है। यह हमारी उस नीति का प्रतीक है कि हम

[श्री राम प्यारे पनिका]

दूसरे देश के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। ग्राज हम दूसरे देश के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो इस का यह मतलब नहीं है कि हम दुनिया में ग्रकेले पड़ गये हैं। जब यहां पर जनता पार्टी की सरकार थी, ग्रमरीका में भारत के राजदूत ने वहां के राष्ट्रपति की मां की चप्पल भी उठाई थी, लेकिन उस के बाद भी हमारे एटामिक पावर प्लांट की समस्या हल नहीं हुई। लेकिन हमारी प्रधान मंत्री जी ने सूझ-बूझ से ऐसी नीति बनाई, ग्रमरीका ग्रौर फ्रांस के साथ मिल कर, कि हमारे तारापुर के एटामिक पावर प्लांट बन्द होने नहीं जा रहे हैं। ग्राज सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत घनिष्ट हैं। यह ठीक है—जैसा राष्ट्रपति जी ने ग्रपने ग्रभिभाषण में चिन्ता प्रकट की है—पाकिस्तान को सोफेस्टीकेटेड हथियार मिल रहे हैं, जिस से इस महाद्वीप के लिए खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन उस के बावजूद भी हम समझौता चाहते हैं, शान्ति के साथ रहना चाहते हैं।

मैं ग्रभी 20 प्वाइण्ट प्रोग्राम के सम्बन्ध में कह रहा था—मेरे एक साथी ने "रामचरित मानस" का उदाहरण दिया था। गीता में भी कहा गया है—जब मनुष्य सब उद्यमों से थक जाय तो क्या करे—

सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज,
ग्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष यश्यामिमाशुच:

मैं ग्रपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं—ग्राइये, जुट कर 20 प्वाइण्ट प्रोग्राम को सफल बनायें। ग्रगर ग्राप भी उसे ग्रपना लेंगे तो देश से विषमता समाप्त हो जायगी, कुव्यवस्था दूर हो जायगी ग्रौर देश बिना किसी रुकावट के उन्नति की ग्रोर बढ़ता जायगा।

ग्रब मैं दो शब्द प्लानिंग कमीशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ....

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में बजट के समय बोलियेगा।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं—प्लानिंग कमीशन ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए 6 प्रकार का ग्राइडेण्टिफिकेशन किया है—डेजर्ट, पहाड़ी क्षेत्र, सूखा, बाढ़, साइक्लोनिक एरिया तथा ट्राइबल एरियाज़। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में ये सब एक साथ ग्रा गये हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश के ग्रधिकांश भागों में यही स्थिति है, फिर भी मिर्ज़ापुर में इस का पूरा प्रभाव है, लेकिन जिस ग्रनुपात में इस समस्या का सामना करने के लिए हमारे प्रदेश को सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली है।

गन्ने का 25 करोड़ रुपया हमारी सरकार नहीं दे पा रही है। सूखे से बचाने के लिए इन्दिरा जी ने जो 12 सूत्री कार्यक्रम देश को दिया है, राज्य सरकारें उस पर काम नहीं कर रही हैं। ग्रब जहां तक विकास कार्यों की बात है ग्राप ने कहा है कि मैं बजट के समय बोलूं, तो ग्राप हमारा नाम नोट कर लें। मैंने ग्रभी ग्राधा भाषण ही दिया है, ग्राधा बजट के समय बोलूंगा।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने संसद् के दोनों सदनों को सम्बोधित किया है इसके लिए हम सब ग्राभार प्रकट करते हैं। तथा उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति के ग्रभिभाषण में वर्तमान सरकार की सफलताग्रों एवं उसकी भावी नीतियों का संकेत

मिलता है। राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सिंहावलोकन करते हुए जिन तथ्यों की ओर हम सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। विषम परिस्थितियों की चर्चा करते हुए उन्होंने सब लोगों से एकता और सद्भाव से समस्याओं के निराकरण की भी अपील की है।

आप सब जानते हैं कि कुछ काल से हमारा देश विषम परिस्थितियों में से गुजर रहा है, असामान्य परिस्थितियों से हमारे देश का समय बीत रहा है। पूर्वांचल में यदि असम क्षेत्रवाद की आग में धधक रहा है, तो उत्तर में धर्म के नाम पर सड़कों पर लड़ाई छेड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। तीसरी ओर दक्षिण में राष्ट्र भाषा के विरोध में तलवारें चमकाई जा रही हैं। यह सच है कि इस में कोई दो मत नहीं हैं कि हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व हैं, हमारे देश में कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं जो कि हमारे आन्तरिक मामलों को बढ़ावा देते रहते हैं, उन्हें उजागर करते हैं, जिस से हमारे देश की जो काया है, वह रुग्ण होती है। अभी हम लोगों ने दो दिनों तक आसाम की स्थिति की चर्चा की। इस सदन में हम सभी सदस्य उस के बारे में बहुत ही गंभीर रूप से विचार-विमर्श कर रहे थे। असम के लोगों की संस्कृति, उस की भाषा सबल हो, मजबूत हो, यह प्रत्येक राष्ट्रवादी चाहता है और हमारी तो यह राष्ट्रीय विशेषता है कि हम अनेकता में एकता चाहते हैं लेकिन हम न तो एकता को कमज़ोर करना चाहते हैं, और न अनेकता को हम खोना चाहते हैं। परन्तु वर्षों तक आन्दोलन हो, चुनाव न कराये जाएं, प्रजातंत्र की हत्या हो, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, इस से हम अपने राष्ट्र और देश की गरिमा की कब तक रक्षा कर सकते हैं, उस की संस्कृति और सभ्यता को क्या बचा सकते हैं। देश में सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उन के सहयोगियों का यह रवैया जरूर रहा है कि जो हमारे धर्म और सम्प्रदाय हैं उन के नाम पर जो हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं उन को बढ़ावा दिया जाए, उन को प्रोत्साहन दिया जाए। असम की समस्या अभी तत्काल ज्वलन्त है। ऐसी राजनीतिक पैंतरेबाजी कर के आग में घी डालने का काम इन लोगों ने किया है और इस से सारी अर्थ-व्यवस्था समाप्त होगी और न केवल असम की बल्कि सारे देश की अर्थ-व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे समय में जब कि हमारे राष्ट्र को तेल की जरूरत थी, उस के उत्पादन को बन्द कर दिया गया था जो कि हमारी आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

अब जरूरत इस बात की है कि विभिन्न समुदायों के बीच, जैसे असमी और बंगालियों के बीच, असमी और इम्मीग्रेण्ट्स के बीच, असमी और कबीले जन-जातियों के बीच प्रेम और सद्भाव को पैदा कर सामान्य स्थिति लाई जाए। जिन लोगों के घर जल गये हैं, उन को बसाया जाए, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गये हैं और जो सब कुछ खो चुके हैं, उन को मनोवैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है और उन को सहानुभूति देने की आवश्यकता है लेकिन इस के विपरीत क्या हो रहा है। उस दिन यहां संसद् में विरोधी पक्ष के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा दर्द और बड़ी भावना जताई लेकिन मैं तो यह कहूंगी कि वे उन के घड़ियालू आंसू थे। उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि हमारी प्रधान मंत्री कौन सी पोशाक

[श्रीमती कृष्णा साही]

पहनती हैं, हमारी प्रधान मंत्री किस भाषा का प्रयोग करती हैं। इन बातों की उन को चिन्ता थी लेकिन उन को वहां के लोगों की चिन्ता नहीं थी और किस तरह से हम इतनी बड़ी समस्या का निराकरण कर सकते हैं जिसके कारण हमारा देश टूटने के कगार पर है, इस की चिन्ता उनको नहीं थी।

आप सभी जानते हैं कि विरोधी पक्ष राष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत नहीं हैं लेकिन आश्चर्य तब होता है जब वे इस मुद्दे पर एकमत हैं कि कसे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा की सरकार को, जोकि एक स्थाई सरकार है छिन्न-भिन्न किया जाए। स्वयं तो टुकड़ों और खण्डों में बंटे हुए हैं और चाहते हैं कि देश भी खण्डों में बंट जाए। यह जो इन का रवया है, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसी साम्प्रदायिक राजनीतिक जमायतें हैं जोकि संकीर्णता का बढ़ावा देती हैं और राजनीतिक तोड़-फोड़ की नीति को अपनाती हैं। मनीपुर, नागालैण्ड, मिजोरम, सभी जगहों पर ऐसी हरकतें हो रही हैं।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं और मैं कोई कटुता की भावना से यह नहीं कहना चाहती। दक्षिण में कांग्रेस की पराजय के बाद ऐसा सुनने को मिला है कि राष्ट्रीय भावना और विकास की प्रक्रिया से वे विमुख हो गये और भाषा और क्षत्रीयता के नाम पर आन्दोलन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ ही दिन पहले वहां एक डिप्रेस्ड क्लास की कान्फ्रेंस हुई थी और मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि राष्ट्रीय स्तर के विपक्ष के नेता ने यह कहा कि "जब तक एक ब्राह्मण केन्द्र का शासन कर रही हैं तब तक आप न्याय की आशा नहीं कर सकते।" इस तरह की जातीयता को उल्टी-सीधी बात कहना धर्म के नाम पर द्वेष फैलाना कहां तक उचित है, यह विचार का विषय है। यह बात किसी छोट-मोटे नेता ने नहीं कही बल्कि एक अखिल भारतीय स्तर के विपक्ष के नेता द्वारा कही गई है, इसलिए मुझे इस बात का और अधिक दुख है।

दूसरा उदाहरण एक संसद् सदस्य का है। इन्होंने एक मांग पत्र पर स्मरण पत्र पर 45 सदस्यों के हस्ताक्षर कराए: हमने अखबारों में पढ़ा, इस मांग-पत्र में लिखा हुआ था कि इस शासन में कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यहां पर मुसलमानों का आर्थिक विकास नहीं हुआ है। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारी सरकार हमारी पार्टी की बुनियाद ही इसी पर आधारित है कि किस तरह से अल्पसंख्यकों की रक्षा की जा सकती है। कैसे मुसलमानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी कैसे रक्षा की जा सकती है और इसका सब से बड़ा उदाहरण यह है कि हमें अपने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को शाहदत को कीमत इन्हीं कारणों से चुकानी पड़ी। श्रीमती गांधी तो आज और भी इस क्षेत्र में दो कदम आगे हैं। हमारी पार्टी ने इसको मूल सिद्धांत के रूप में माना है और मुसलमानों और अल्प संख्यकों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके कारण कई बार श्रीमती गांधी को दूसरे वर्गों का कोपभाजन भी बनना पड़ता है और कुछ लोग उनके बारे में उल्टी-सीधी बातें भी किया करते हैं। श्रीमती गांधी सदैव ही समाज के कमजार वर्गों, मुसलमानों का आगे बढ़ाने के लिए और समाज में समानता के लिए प्रयत्नशील रहती हैं।

हमारे माननीय सदस्य श्री जेठमलानी साहब बहुत जोर-शोर से भ्रष्टाचार का बात कर रहे थे। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उनको केवल भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है, हमारी उपलब्धियां उनको दिखाई नहीं देतीं। मुझे और भी दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि हमारे प्रशासन में, हमारी पार्टी में सिर्फ भ्रष्ट मुख्य-मंत्रियों को ही संरक्षण दिया जाता है। लेकिन वे शारद* साहब का नाम कहना भूल गए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, जिनके ऊपर चार्जशीट हो चुकी है, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। उनकी चर्चा यदि वे करते तो मैं समझती कि उनके हृदय से यह भावना निकल रही है। लेकिन ऐसा नहीं था : उनके भाषण से राजनीति की बू आ रही थी। उनकी कोशिश यही थी कि किस तरह से हमारी पार्टी पर काला धब्बा लगाया जाए।

हमारे देश में गरीबी है, निरक्षरता है, हमारे विकास का स्तर नीचा है, लेकिन हम बुनियादी तौर पर खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हो चुके हैं। फिर भी हमें और अनाज उत्पन्न करना है। हमने मंजिलें बहुत पार की हैं, लेकिन फिर भी हमारी बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे आर्थिक विकास की गति कुछ कमजोर हो गई है। बढ़ती जनसंख्या को बाढ़ में आर्थिक विकास की इमारत कुछ कमजोर हो गई है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1977 में हमारी पार्टी की हार के लिए यह मुद्दा बनाया गया था कि जिस तरह से परिवार नियोजन के कार्यक्रम को धक्का लगाया जाए। अगर इन राष्ट्रीय मुद्दों पर विकास ने हमारा साथ दिया होता तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। इसी प्रकार भूमि-सुधार कार्यक्रम की भी विरोधी दलों द्वारा कटु-आलोचना की गई। देहात में लोगों को गुमराह किया गया। इस सम्बन्ध में नारा दिया गया "स्वास्थ्य गया नसबन्दी में---खेत गया चकबन्दी में" देहात में इस तरह का प्रचार किया गया। मैं कहना चाहती हूं कि यदि इन राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को साथ दिया होता तो आज हमारी आर्थिक स्थिति कुछ और होती।

हमारे विपक्ष के लोगों को यह सबसे बड़ी उपलब्धी दिखाई नहीं पड़ती कि तारापुर को छोड़कर हमारा सारा देश ईंधन में आत्मनिर्भर हो गया है। माननीय सदस्य समर मुखर्जी ने भी कहा था कि तीसरी दुनिया में भारत एक-मात्र ऐसा देश है जिसने विपरीत परि-स्थितियों में भी मूल्य-वृद्धि और मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण रखा है। विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए हमारी प्रधान मन्त्री किस तरह से कंसन्र्ड हैं, इसे सभी जानते हैं। वैज्ञानिकों को जो जत्था अन्टारटिका पर गया, यह अपने में एक अनोखी घटना है। सुरक्षा के क्षेत्र में मेनबैटल टैंक की कहानियां सुनी-सुनाई जाती हैं। लेकिन इस वर्ष के अन्त में जब प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तब लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे वैज्ञानिक किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों से हाथ मिलाने में पीछे नहीं हैं। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो बड़े देश हैं, उनमें हमारी गणना होती है विश्व के 92 औद्योगिक बड़े देशों में हमारी गिनती है। राष्ट्र की महिमा और गरिमा का प्रदर्शन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था जब एशियाई खेलों का आयोजन किया गया

[श्रीमती कृष्णा साही]

था । यह देश की क्षमता और दक्षता को प्रमाणित करता है । जिस प्रकार इन्सान को सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि कला और मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे देश को भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सदभाव अवश्य चाहिए यह बुनियादी है दूसरे लोगों से मित्रता और सद्भावना बढ़ाने के लिए । ब्रिटेन में जो इन्डिया फैस्टीवल हुआ उसमें भारत की संस्कृति सभ्यता और भारत ने किस तरह से प्रगति की है आदिकाल से लेकर अब तक का इतिहास दिखाया गया था । सारे विश्व के लोग वहां जाते थे और भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे कि किस तरह से हमारा देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है । गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन भी हमारी गरिमा का द्योतक है । श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र की छवि मुखरित हुई है । विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में वृद्धि हुई है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । सन् 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने हमारे देश की छवि को सिर्फ धमिल ही नहीं किया था बल्कि अन्तराष्ट्रीय क्षितिज पर भी हमारे राष्ट्र को हंसी का पात्र बना दिया था ।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि हम सभी लोकतंत्र में रह रहे हैं । हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए । हमारा यह प्रथम कर्त्तव्य है । कई मसलों पर मतभेद हो सकते हैं परन्तु ये मतभेद देश की कीमत पर नहीं होने चाहिए । अपने मत-मतान्तरों को भूलकर राष्ट्रीय विकास के महायज्ञ में पक्ष और विपक्ष सभी को मिलकर पूर्ण सहयोग करना चाहिए । हमने आन्तरिक प्रतिकूल परिस्थितियों में अन्तराराष्ट्रीय दबाव में, प्राकृतिक प्रकोप के बावजूद भी एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे हमारा देश प्रगति के द्वार पर खड़ा है और विकासशील देश से विकसित देशों की गणना में हमारा देश आने वाला है । हमारे देश में जरूरत इस बात की है कि इंजीनियर, डाक्टर मजदूर एवम् युवा वर्ग को सही नेतृत्व मिले । मुझे विश्वास है कि एकमात्र श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ सकता है और विकास कर सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं और सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूं ।

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Madam Chairman, in his Address the President has dealt with a number of political, economic snd social issues and many of my Parliamentary colleagues have dealt with these in great depth. A great deal could be said about them. It is a mixed picture. There are certainly considerable achievements, such as the Asiad and there are also failing. But Madama, within the limited time at my disposal, I will say a few words on a matter about which the Address is silent. I think that is a serious omission. I am referring, of course, to the precipitated erosion of moral and spiritual values in al lspheres of activity of this country.

16 hrs.

I am not now talking about invidual cases of corruption here and there. What I am saying is that a nation, founded upon the principles सत्यमेव जयते of and behind your seat धर्मचक्र प्रवर्तनाय based upon the idealism of some of the greatest sages and thinkers of this century, as far back as Sri Aurobindo, Lok Manya Tilak and Mahatma Gandhi, a nation which came into being on the basis of certain moral and

spiritual values, should today have virtually been converted into a moral wasteland.

In fact, I have been travelling very extensively in this country for the last two years, and have visited a large number of States and towns. And almost everywhere one goes, one is met with the remark that corruption today has virtually become a way of life; it is now no longer something which is to be fought or which is to be discouraged, it is beginning to become accepted as a way of life in India. I would like to say that this is a great tragedy, and it is beginning to have an adverse impact now upon our political life and upon our economic devlopment. Because, when there is corruption, the amount of money spent upon any project, does not all go into the development of that particular project; so also in our administration and in all spheres of life.

Now what are the reasons for this? Partially, of course, whenever a traditional society breaks down due to socio-economic causes, the rigid framework of values necessarily collapses, and certainly that has to be accepted. In a way, it is welcome, because there is no desire to go back to a rigid framework of an outmoded age. But nonetheless, I think you will agree, and I think my colleagues from all sides of the House will agree, that if a nation loses its moral perspective, if it loses the spiritual impetus behind it, ultimately that nation cannot achieve greatness; howsoever rich it may be in material terms, it will not really achieve what may be called greatness.

Now what is happening here? With the breakdown of the joint family, the old value system has disappeared and there is no replacement. Our educational system, in the last 35 years since we became independent, has become entirely devoid of any value. There is no value-system any longer in our schools and colleges. I think this is the result of a wrong interpretation of secularism. With secularism we have thrown the baby out along with the bathwater. We are so afraid that we will be accused of teaching religion that we have made our educational system totally devoid of any moral and ethical ideas, of the teachings of the Upanishads or other scriptures. All great religions have ideals behind them. Does secularism mean that we have to deprive the children of India of an awareness of these ideals? Where will the value system go with the break down of the family, when your schools and colleges do not give any moral or spiritual education?

In adition, there are these films which today have become one of the major factors in eroding whatever values whatever system of ideals may exist in this country. It is a blatant exploitation of the younger generations by people who make lakhs and crores of rupees in these films, which are mostly financed through black money. Horror, rape and violence are glorified. Wherever you go, if you go to any city in India, you will find this sort of film going there, and nothing is done to stop this trend. So, on the one hand, you have an educational system devoid of any values; on the other hand, you have constant erosion, mainly due to films that glorify violence, hatred, horror and rape, and this sort of undesirable social activities. What then do we expect our younger generations to do?

There is the question of electoral reforms. One of the major reasons for corruption in this country, and this is well-established, is very high cost of elections. The company donations have not been legalised. As a result of this, every serious political candidate of parties is dependent, sooner or later, upon funds that are unaccounted. What are you doing about it? No less a person than the former Chief Election Commissioner, Shri S. L. Shakdher, has made the suggestion that we should move towards State financing of elections. And I think he said that a fund of about

[Dr. Karan Singh]

Rs. 100 crores should be able to meet the requirements. We spend a hundred crores of rupees on one jumbo jet. Would it not be better to bring about necessary electoral reforms so that this corrosive reliance upon unaccounted money is at least brought within reasonable limits? None of the Ministers are here today, I am told that they had to go for a pre-budget Cabinet meeting, but I hope the Prime Minister is going to read what we are saying here. My point is that we must give attention to this problem. We must, first of all, move to introduce some sort of value system in our education. There have been committees; you may remember, the Sri Prakasa Committee, the Dr. Radhakrishnan Committee, the Kothari Committee and numerous committees of the Government of India have suggested that there should be an introduction of moral and spiritual education, but nothing is being done. Why can we not make a start? Why can the Government of India not make a start in the Central Schools, in the Sainik schools that come directly under the Education Ministry and thereby, as it were, blaze the trail which the States could then follow? So, my first point is that we must prevent this rot. Otherwise the younger generation are growing without any type of guidance.

Secondly, there is the question of these films. I have raised this earlier also, but either there is a very strong lobby or there is lack of awareness on the part of the Government. Why are steps not being taken to curb this violence and horror in the films. I would like to know. Day in and day out the consciousness of the younger generation is being polluted and nothing is being done. If somebody were to pollute our water supply with a slow poison, everybody would be upon his feet demanding urgent action. I would like to ask you, Madam, and through you my colleagues: Is the pollution of the mind less dangerous than the pollution of the body? Why is something not being done about this? Why can the Government of India not move in this matter? Why can't the Prime Minister herself with all the tremendous power and influence that she commands, take up this matter herself?

Thirdly, there is a question of electoral reforms which has to be given priority. As an Independent Member I would appeal both to the Ruling Party and to the Opposition parties that they should get together urgently and introduce some substantial reforms before the 1985 elections so that we can move out of this pathetic dependence upon unaccounted money that is today the fact of life.

And then, Madam, of course, mainly it is a question of personal example. My friend here was quoting the *Bhagvad Gita*. There is a very well known sloka in the *Bhagvad Gita* which says:

यत यताचरति श्रेष्ठसतत ततेवितरो जना:

सयत प्रमाणम् करुते लोकस्ततनुवतते ।।

What the leaders do, the people will follow. The *pramana*, the sort of example that we set—when I talk of leaders, I am not necessarily talking of leaders of any political party or Government, but leaders of society whether it is in politics, whether it is in business or whether it is in labour or anything. We have got to set an example for the younger generation. It is only if this happens, Madam, that there is any chance of a spiritual and moral regeneration in India. And I would conclude by saying that this regeneration is required not only for India—Madam, today mankind is at cross-roads in its long and tortuous history on this planet.

Science and technology has given a tremendous power, a power which can be used with wisdom and compassion, and a power which can be used with hatred also. If it is used wisely, we can abolish poverty, want and illiteracy and disease from the face of the earth If it is misused, the human race itself may be abolished. There is this growing divergence between knowledge and wisdom, which has to be bridged. We

need a new bridge between science and philosophy and it is my conviction that India alone, of all countries of the world can bring about this synthesis because we have an unbroken philosophical tradition going back to the dawn of history, and we also have the third largest pool of the scientists in the world. We have never been a country which is living for ourselves alone. India's message in the ancient days, its philosophising message spread throughout the length and breadth of Asia and South-East Asia.

I went to Bali a few months ago, I went to Indonesia. I went to Java, 99 per cent Muslim countries, but the impact is of Indian culture there. The Ramayana is better known in Bali and Java than in many parts of this country, because there was a moral force value that was behind the Indian civilisation. We need that sort of synthesis. We have got to bring about this convergence between Science and Philosophy. But how can we do if we are not able to re-capture our own moral and spiritual roots. Therefore, while speaking on the President's Address I would like to mention this point the absence of which has irked me—if I may paraphrase one of Faiz Saheb's verses:

वह बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था
वह बात मुझ को बहुत नागवार गुजरी ।

I did not like the absence of any moral dimension to the President's Address. I would urge the Prime Minister when she replies; we have made great economic progress, we have made progress administrative problem; in the international sphere, we are hosting a great Conference, but are we in danger of losing our soul? Are we in danger of losing those moral and spiritual ideals that are behind the Indian civilisation and with which alone India can reach her full stature not only for hereself but for the whole of mankind.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है उस पर रेड्डी साहब ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह वर्ष हमारे लिए बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ है । जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे और अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक हम इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे । इसलिए हमें अनुशासन में रहकर अपने कामों में जुट जाना चाहिए ताकि हम इस देश की गरीबी को दूर कर सकें ।

हमारी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं वह भी बहुत हैं । उसने आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से रोका है, इंफ्लेशन को बढ़ने से रोका है और कीमतों को भी बढ़ने से रोका है । जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं उनका सरकार दृढ़ता से मुकाबला कर रही है ।

आज सबसे प्रमुख समस्या सूखे की है । सरकार ने इसके लिए 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है जोकि एक प्रशंसनीय बात है । प्रान्तीय सरकारों को यह देखना चाहिए कि सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों को रोजगार धंधा मिलता है या नहीं । 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बाद भी अगर लोगों को रोजी-रोटी न मिले तो इस रुपए की कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी । केन्द्रीय सरकार को मानीटियरिंग करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस पैसे का प्रान्तीय सरकारों द्वारा सही तरीके से उपयोग होता है या नहीं और उसमें कोई बेईमानी तो नहीं होती है और जिनके पास तक वह पैसा जाना है वहां तक पहुंचता है या नहीं । यदि ऐसा नहीं होगा तो गांव के गरीब लोग भूख और प्यास से मर जायेंगे । श्रीमती इन्दिरा गांधी पर हमें पूरा विश्वास है । वे जो कुछ कहती हैं वह करती भी हैं । लेकिन कुछ प्रान्तीय सरकारों की वजह से ठीक व्यवस्था नहीं हो पा रही है । मैं अपने ही प्रान्त की बात कहना चाहता हूं । वहां पर

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

इतना भीषण अकाल है परन्तु एक एक जिले में केवल 10—15 हजार लोगों को ही काम दिया गया है । आज सारे देश में 33 करोड़ लोग गरीबी की सतह से नीचे हैं और हमारे राजस्थान में साढ़े तीन करोड़ की आबादी में पौने दो करोड़ ऐसे हैं जो गरीबी की सतह से नीचे हैं । जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यदि उनके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था न करें, पीने के पानी की व्यवस्था न करें, उनके जानवरों के लिए घास की व्यवस्था न करें, तो वे जीते-जागते मर जायेंगे और वह कलंक हमारे सरकार के सिर पर आएगा । इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां-जहां की सरकारें अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही हैं, गरीबों की सहायता नहीं कर रही हैं, उन पर हमें अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से यह बदनामी हमारी सरकार के ऊपर आयेगी । इसी प्रकार फैमिन रिलीफ के कामगाज के लिए मोनिटियरिंग भी भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए । आज जो बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हैं, ये उस सारे पैसे को डकार जाते हैं, उस पैसे का फायदा उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है । मैं राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, मगर सात सौ करोड़ रुपया वहां तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इसकी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए । प्रान्तीय सरकारों पर अंकुश लगाकर पूरे का पूरा पैसा उन गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहिए ।

दूसरा निवेदन यह है कि सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाया, सीमेंट का उत्पादन बढ़ाया, फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाया, लेकिन बिजली के संबंध में राजस्थान की क्या हालत है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान पिछले चार-पांच सालों से भयंकर बजली की कटौती का शिकार हो रहा है । हर साल 500 करोड़ रु० का नुकसान है । आज तमाम बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज बन्द पड़ी हुई हैं । सारे मजदूर बेकार हैं । उनकी रोजी-रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है । पांच सौ करोड़ रुपए का एक प्रान्त को नुकसान हो रहा है, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं । इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें पंजाब से पूरी बिजली नहीं मिल रही है, मध्य प्रदेश से भी बिजली नहीं मिल रही है, बदरपुर से भी बिजली नहीं मिल रही है, सिंगरौली से भी बिजली नहीं मिल रही है । 220 लाख यूनिट एक दिन का खर्च है, जिसमें से 90 लाख यूनिट रोज मिलती है, जिसकी वजह से वहां का काश्तकार बहुत परेशान है । इसी बिजली के अभाव में वहां की फसलें बर्बाद हो रही हैं । हमें वहां पर बिजली की व्यवस्था होने की कोई आशा की किरण भी नहीं नजर आ रही है । हमारे दोनों आर० ए० पी० पी० के इंस्टालेशन बन्द पड़े हुए हैं । साल में 20—25 दिन चलते हैं, जो कि कुल 420 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं । लेकिन आज वे बन्द पड़े हुए हैं । राजस्थान का थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी काफी दिनों से शुरू नहीं हो पा रहा है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बिजली की व्यवस्था कराइए । जिस प्रकार 1977 में लोग फैमिली प्लानिंग की वजह से नाराज हुए थे, उन्होंने हमारी सरकार को एक बहुत बड़ा धक्का दिया था, उसी प्रकार की हालत आज बिजली की वजह से पैदा हो रही है । आज काश्तकार के मन में इस प्रकार के असंतोष की भावना है । इस प्रकार के असंतोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि उनको बिजली की सप्लाई करो, ताकि वह अपनी खेतीबाड़ी की पदावार को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे और गरीब मजदूर जो बिजली की कमी की वजह से

रोटी से वंचित हो रहे हैं, उनको कल-कारखानों में काम करने का मौका मिले और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें ।

सभापति जी, अब मैं थोड़ा राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । इन अकालियों ने जिस प्रकार की मांग रखी है कि रावी-व्यास के पानी के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था उसको समाप्त करके नई व्यवस्था की जाये—हम इसका घोर विरोध करते हैं । आप, सभापति महोदया अच्छी तरह से जानती हैं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और इसका आधे से ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान है । 1955 में जो फैसला हुआ था, उस के बाद उसमें थोड़ा-बहुत संशोधन करके 1981 में जो फैसला हुआ था, उसके अन्तर्गत हमको 89 लाख घनफुट पानी मिलना तय हुआ था, लेकिन अब उस एग्रीमेंट को बदलने की बात करते हैं और भारत सरकार को धमकी देते हैं कि अगर यह एग्रीमेंट नहीं बदला गया तो हम आन्दोलन करेंगे, हम संघर्ष करेंगे । क्या राजस्थान के लोग इस संघर्ष से पीछे रह जायेंगे ? राजस्थान कभी पीछे नहीं रहेगा, अगर आप ने हमारे पानी के हिस्से को कम किया तो हम निश्चित तरीके से संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे लिये यह जीवन-मरण का प्रश्न है । अगर राजस्थान को पानी नहीं मिलता है तो राजस्थान के इलाके सूखे रह जायेंगे और यह राजस्थान के करोड़ों लोगों के लिये जीवन-मरण का प्रश्न बन जायगा । इसलिये मैं आपकी मारफत भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप रावी-व्यास समझौते में किसी प्रकार का बदलाव न लायें और इन अकालियों के सामने इनकी धमकियों से नहीं डरें । हम आपके साथ हैं, जीवन-मरण में सब प्रकार से आपके साथ हैं, जहां पर आपका एक बूंद पसीना गिरेगा हम वहां अपना खून बहा देंगे । इसलिये हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हिस्सा है, उस हिस्से के सम्बन्ध में यदि आपने किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय ले लिया तो उसके लिये राजस्थान पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा । इसलिये इस सम्बन्ध में आप खास तौर से ध्यान रखें । राजस्थान की विधान सभा ने भी एक मत से इस सम्बन्ध में निर्णय किया है, प्रस्ताव पास किया है कि राजस्थान का हिस्सा कम नहीं होना चाहिये, पूरा पानी राजस्थान को मिलना चाहिये । इसलिये इस सम्बन्ध में आप विशेष ध्यान रखें ।

एक बात मैं पीने के पानी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । राजस्थान में पीने के पानी का भयंकर अभाव है । भारत सरकार की तरफ से इसके लिये काफी सहायता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, मैं इसके लिये भारत सरकार को धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन जो इम्प्लीमेन्टेशन की एजेन्सी है वह बहुत निकम्मी है । विधान सभा में भी इससे सम्बन्धित घुटालों के सम्बन्ध में आवाज बुलन्द की गई थी कि पीने के पानी के लिये जो रुपया भारत सरकार से मिला है उसमें बहुत घुटाला हुआ है, उसकी जांच करानी चाहिये, 25 करोड़ रुपये का घुटाला हुआ है । इसी तरह से राजस्थान कैनाल बनाने में 200 करोड़ रुपये का घुटाला हुआ है, जिसकी रामसिंह कमीशन ने जांच की थी । ये दोनों राजस्थान के लिये जीवन-मरण का प्रश्न हैं, इसलिये हमारा अनुरोध है कि जो घपले हुए हैं उनकी तुरन्त जांच करवाई जाय और ऐसी व्यंवस्था की जाय जिससे राजस्थान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके ।

राष्ट्रपति जी ने जितने प्वाइन्ट्स अपने अभिभाषण में रखे हैं वे बहुत अच्छे हैं, मैं उन सब का समर्थन करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack): Madam Chairman, the President's Address is brief and yet it effectively touches upon all the important facets of national life and activity.

[Smt. Jayanti Patnaik]

The President has mentioned in his Address about our significant gains and the difficult times our country is facing on account of international situation and some burning national problems. The President has also described the political, economic and social strategies that we have adopted to meet the situation.

The international arena is today in a flux; the confrontation between Super Powers has reached a new height snd, specially, the other disturbing areas, including the Middle East, pose a global problem. Across our borders; thtre is a serious armed build-up threatening our security. In this context, the Seventh Non-Aligned Summit which is being held next month in New Delhi is of great significance. I must congratulate our Prime Minister for holding the Conference in New Delhi. Of course, it was to be held in Baghdad.

But all the nonaligned countries desired to hold it in India and this shows the height of prestige at which the other countries hold India and our leader.

I must also congratulate our Prime Minister for projecting our policy of non-alignment and peaceful co-existence successfully in the international sphere.

We are faced with two major problems. One is political situation in Assam and Punjab and the other is the economic problem or challenge posed to us by the unprecendented natural calamities including the serious drought situation in wide part of the country.

It is a tribute, of course, to the democratic system and also to the Government committed to democracy that elections due in many of the States have been held and the people have given their virdict freely.

We have already made it clear that, to find solutions to the problems of Assam and Punjab, we have lost no opportunity in involving all the opposition parties.

Unfortunately, the attitude of the opposition parties has become ambivalent. The election in Assam was inevitable because of the constitutional requirement.

It is not the Congress party which is responsible for the problem that arose in Assam. It is the Janata Party which is responsible for this problem because they could not deal with the problem at their time and they created this problem. In addition to that, the support given to them by certain other opposition parties, has aggravated the situation.

I hope that the situation will stabilise as a Government of elected representatives of people has come to power and that a satisfactory solution of the problem would be found.

I hope that the satisfactory solution of the problem of Punjab also would be found.

The opposition parties should cooperate with the ruling party on national problems.

In spite of widespread drought and other natural calamities which required a record level of Central assistance of Rs. 700 crores for relief work, we can find signs of a healthy trend in our economy.

The 20-point programme has made significant strides, particularly in programmes for the benefit of the poor. In spite of raising inflation throughout the world, we have succeeded in containing inflation in our own country.

India is one of the oil-importing countries which, through these long years, has maintained the tempo of planned development and achieved a significant reduction in the rate of inflation.

The wholesale price index has also increased only marginally. During the last one year, a relative price stability has been achieved in spite of contra-seasonal increase in the prices due to erratic rains and drought situation.

The demand and supply position in respect of cement is evenly balanced.

In respect of several essential commodities, the public distribution system has become an important instrument for supply-management effort. This has helped in mitigating the disastrous effects on the prices of several commodities in the country.

MR. CHAIRMAN: You can continue tomorrow, now the time is over. Shri Xavier Arakal will make a statement under rule 377 now announced by the Speaker. Then we will adjourn far half-an-hour.

16.28 hrs.

MATTER UNDER RULE—377—*Contd.*

(viii) NEED FOR A FOREIGN AIRMAIL SORTING OFFICE AT COCHIN

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): I raise the following matter under rule 377:—

Kerala State is the most thickly populated and litrate State of the Union of India. Many Keralites have gone abroad in search of jobs and many have settled down in various countries throughout the world, these Keralites remit vdaluable foreign exchange to the tune of Rs. 200 to Rs. 400 crores a year to the Central exchequer. There is a large foreign correspondence in the State which requires the immediate attention of this Government. There is an urgent need for a full-fledged Foreign Air Mail Sorting Office to meet the needs of the Keralites.

Cochin is the *de facto* capital of the State. There is already an understaffed an infrastructure at Cochin. It has mail sorting office. Moreover, Customs House, air and sea-ports, many industrial and institutional establishments, etc., are situated at Cochin. Above all, it is the central point of departure and arrival of passengers and goods.

Therefore, I urge upon the Government to convert the existing foreign airmail inward sorting office into a full-fledged foreign airmail sorting office and staff it immediately so that delay and hardship can be avoided.

MR. CHAIRMAN: As announced earlier, the House stands adjourned to reassemble at 5.00 p.m. today for the presentation of the General Budget.

16.30hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

BUDGET (GENERAL) 1983-84

MR. SPEAKER: The hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I rise to present the Budget for the year 1983-84.

2. The Economic Survey for 1982-83, placed before the House a few days ago, has given a detailed account of the trends in Indian economy during the curret year. I shall, therefore, be brief in reviewing the economic situation.

3. A drought year is always a difficult one for the economy. The decline in agricultural production that the drought entails has an effect which goes beyond the rural sector. The drop in the purchasing power of our farmers exerts a deflationary influence on industry. The drought also affects power generation and has an adverse impact on the external payments. It